www.twnews.in / RNI No.UTTHIN/2015/68784

हिन्दी मासिक पत्रिका

टाईम विटनेस

सभी प्रदेशवासियों को नव वर्ष, मकर संक्रांति, लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनायें।

वर्ष:5 अंक :06 जनवरी 2020 मूल्य : रू 15/-

क्योंकि हम उठायेंगे आपकी आवाज!

NRC CAA

डेमेज कंट्रोल में जुटी सरकार

zomato
SAEED HOTEL
Family Restaurant
MENU CARD
★Breakfast ★Lunch
★Dinner
Contact Us: 8192808080
7669777786,7533857373
43, Gandhi Road, Inamulla Building, Dehradun

समस्त देश व प्रदेश वासियों को
नव वर्ष
2020
लोहड़ी व
मकर संक्रांति की
हार्दिक
शुभकामनाएं
हाजी सुलेमान अंसारी
वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं
पूर्व ग्राम प्रधान, मेहूवाला माफी

समस्त प्रदेश व
देशवासियों को
नव वर्ष 2020
लोहड़ी एवं
मकर संक्रांति की
हार्दिक शुभकामनाएं
समीर पुण्डीर
पूर्व ग्राम प्रधान चालंग,
न्यायपंचायत गुजराड़ा

समस्त प्रदेश व देशवासियों को
नव वर्ष 2020
लोहड़ी एवं
मकर संक्रांति की
हार्दिक
शुभकामनाएं
अभिषेक पंत
पार्षद, वार्ड 60 डांडा लखौंड

समस्त प्रदेश व
देशवासियों को
नव वर्ष 2020, लोहड़ी
व मकर संक्रांति की
हार्दिक शुभकामनाएं
पंकज मैसोन
युवा नेता, भाजपा उत्तराखण्ड

PRAYAG IAS Academy

Uttarakhand's Leading Institute for IAS/PCS, PCS (J)
Prayag IAS College Maan Singh Waala, Dehradun, Ph. No. 0135-2744550

R.A. Khan
Director

आरएनआई संख्याः UTTHIN/2015/68784

टाईम विटनेस

मासिक पत्रिका वर्षः 5 अंक : 06

जनवरी 2020

सह संरक्षक	डॉ. संजय गांधी
विशेष सलाहकार	विजय खण्डूड़ी
कानूनी सलाहकार	मनमोहन कण्डवाल (एडवोकेट)
संपादक	अफरोज़ खाँ
गढ़वाल प्रभारी	अशोक रावत
पछवादून प्रभारी	संजय कुमार
व्यवस्थापक	मेघराज सिंह राठौर
एनसीआर प्रभारी	ए.के. राना
ब्यूरो चीफ, देहरादून	इकराम अंसारी
संवाददाता	बाबू हसन
लेआउट डिजाइनर	शिखा बिष्ट

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अफरोज खाँ द्वारा प्रितिका प्रिंटर्स, 9 प्रगति विहार, धर्मपुर, देहरादून से मुद्रित कराकर, शर्मा कॉलोनी, ब्राहमणवाला, निरंजनपुर, देहरादून, उत्तराखण्ड से प्रकाशित।

संपादक अफरोज खाँ

पत्रिका से संबंधित किसी भी वाद-विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जिला- देहरादून ही मान्य होगा।

अन्दर के पृष्ठ में

10 नमाजियों वाली टोपी पहनकर कर रहे थे पथराव

14 दून को स्मार्ट सिटी बनाने की पहल

16 सरकार के लिए चुनौतियों का अम्बार रहेगा 2020

कार्यालय टाईम विटनेस

नियर रिवरेन पब्लिक स्कूल, ब्राहमणवाला, निरंजनपुर, देहरादून, उत्तराखण्ड
मो0 7409293012, 9084366323
ई-मेलः timewitness2015@gmail.com, afrojkhan78600@gmail.com

नोटः जरूरी नहीं कि लेखक के लिखे लेख से सम्पादक सहमत हो, एवं सभी पद परिवर्तनीय है व सभी सदस्य अवैतनिक है।

उम्मीद है 2020 अच्छा गुजरे

सरकार के सामने कई अहम मुद्दे हैं लेकिन अपनी कमियों को छिपाने के लिए दुसरे देश की कमियों को दिखाने में लगी है

नये साल की शुरूआत काफी अफरा तफरी में हुई, जहां एक तरफ देश के कई हिस्सो में नये साल का आगाज बड़ी धुमधाम से हुआ, वहीं दिल्ली के जेएनयू और शाहीन बाग इलाके में एनआरसी और सीएए के विरोध में धरना प्रदर्शन में नारे लगाकर और राष्ट्रगान गाकर नये साल की शुरूआत की गई। वैसे भी पूरी दुनिया में ऐसा देश कहां मिलेगा जिसका प्रधानमंत्री और गृहमंत्री अपने देश की जनता की चिंता छोड़कर दुसरे देश की जनता को लेकर गंभीर हो। अपने देश के बच्चे भले ही कुपोषण का शिकार हो, लेकिन दुसरे देश की जनता को अपने देश में नागरिकता देने का संदेश दे रहा हो। बीते साल की बात करें तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति क्या थी यह किसी से छिपी नहीं है, रोजगार का तो पता ही नहीं चला, जीडीपी तो अपने पड़ोसी देशो (पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका) से भी नीचे चला गया है, साल के अंत तक पूरे देश में हिंसा व झड़प देखने को मिला। आज सरकार के सामने कई अहम मुद्दे हैं लेकिन अपनी कमियों को छिपाने के लिए दुसरे देश की कमियों को दिखाने में लगी है और इसमें देश के नामी गरामी मीडिया हाउसेस पूरी जी-जान से सरकार का सहयोग कर रही है। हम अपने देश की तुलना ऐसे देश से करने लगे हैं जो कभी दूर-दूर तक हमारे देश के सामने नहीं ठहरता था। क्या हमारा देश आगे की तरफ बढ़ रहा है या पीछे की तरफ जा रहा है? आशा है कि इस साल सरकार देश की अर्थ व्यवस्था, बेरोजगारी जैसे अहम मुद्दो पर भी कार्य करेगी न सिर्फ उन पर काम करे जिसकी वजह से हिन्दु-मुस्लिम के बीच खाई पैदा करने का संदेश जाता हो।

कोहिनूर आर्ट ज्वैलर्स

एक अनमोल रिश्ता | सोना, चांदी के जेवरातों के विक्रेता

अब बेटी की शादी के जेवर की चिंता छोड़ें कोहिनूर आर्ट ज्वैलर्स से नाता जोड़ें

68 माजरा, सहारनपुर रोड, देहरादून फोन न0 0135-2726569, मो. : 9837359716

!! ॐ नमो: भगवते वासुदेवाय नमः !!

नकली दुकानदारों से सावधान

पटाखों के होल सेल विक्रेता

PAWAN ANAND

ANAND Fire Works

पटाखे ही पटाखे

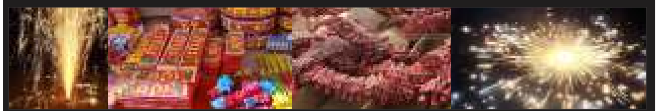

43, Dhamawala Bazar, Near Masjid, Dehradun

M.: 9837374752, 9756553790, 0135-2711681

NO SMOKING

SUPERGAS™

RAVISH GAS AGENCY

Authorized of SHV ENERGY Pvt. Ltd.

Add.: Mittal Colony, Majra Dehradun

8192808080, 9760666130, 7248252648

समस्त प्रदेशवासियों को नव वर्ष 2020

लोहड़ी एवं मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं

शहताब चौधरी

समाजसेवी

सभी देश व प्रदेशवासियों को

नव वर्ष 2020

लोहड़ी एवं, व मकर संक्रांति की

हार्दिक शुभकामनाएं

हाजी सलीम अहमद

प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अ०स० मोर्चा, भाजपा

NRC और CAA

डेमेज कंट्रोल में जुटी सरकार

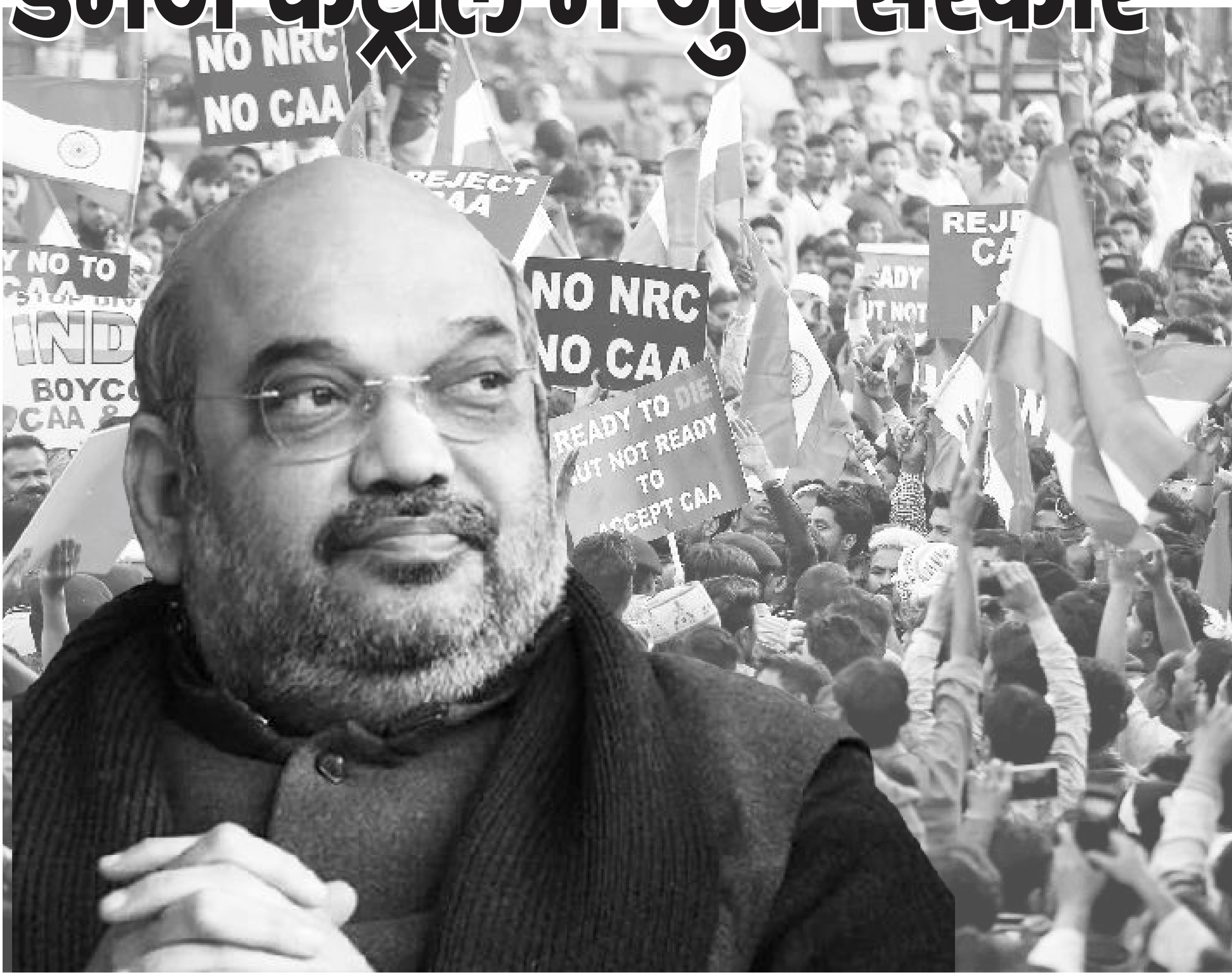

अफरोज खाँ
सम्पादक

नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन (एनआरसी) और नागरिकता संसोधन कानून (सीएए) को लेकर पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल है। कोई इसका विरोध कर रहा है तो कोई इसके समर्थन में रैलियां निकाल रहा है। सरकार हो या विपक्ष दोनो ही सड़को पर उतर गये हैं।

अगर हम एनआरसी की बात करें तो इसकी शुरूआत 2013 में सुप्रीम कोर्ट की देख–रेख में असम में हुई थी, जो अगस्त 2019 तक पूरा हो चुका है जिसके अनुसार 19,06,657 लोग एनआरसी लिस्ट से बाहर हो चुके हैं।आसान भाषा में हम एनआरसी को असम में रह रहे इसे भारतीय नागरिकों की एक लिस्ट के तौर पर समझ सकते हैं। ये प्रक्रिया दरअसल राज्य में अवैध तरीके से घुस आए तथाकथित बंगलादेशियों के खिलाफ असम में हुए छह साल लंबे जनांदोलन का नतीजा है। इस जन आंदोलन के बाद असम समझौते पर दस्तखत हुए थे और साल 1986 में सिटिजनशिप ऐक्ट में संशोधन कर उसमें असम के लिए विशेष प्रावधान बनाया गया।

असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजेंस (एनआरसी) को सबसे पहले 1971 में बनाया गया था ताकि ये तय किया जा सके कि कौन इस राज्य में पैदा हुआ है और भारतीय है और कौन पड़ोसी मुस्लिम बहुल बांग्लादेश से आया हुआ है। इस रजिस्टर को पहली बार अपडेट किया जा रहा है। इसमें उन लोगों को भारतीय नागरिक के तौर पर स्वीकार किया जाना है जो ये साबित कर पाएं कि वे 24 मार्च 1971 से पहले से राज्य में रह रहे हैं। यह वो तारीख है जिस दिन बांग्लादेश ने पाकिस्तान से अलग होकर अपनी आजादी की घोषणा की थी।

इन डॉक्युमेंट्स का होना जरूरी

असम के लोगों को सूची ए में दिए गए कागजातों में से कोई एक जमा करना था। इसके अलावा दूसरी लिस्ट बी में दिए गए डॉक्यूमेंट्स में से किसी एक को दिखाना था, जिससे आप अपने पूर्वजों से संबंध साबित कर सकें। इससे पता चलेगा कि आपके पूर्वज असम के ही थे। अगर असम का फॉर्मूला पूरे देशभर में लागू होता है तो निम्नलिखित दस्तावेजों की जरुरत पड़ेगी।

लिस्ट ए में मांगे गए मुख्य दस्तावेजों की लिस्ट

1951 का एनआरसी, 24 मार्च, 1971 तक का मतदाता सूची में नाम, जमीन का मालिकाना हक या किराएदार होने का रिकॉर्ड, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, शरणार्थी पंजीकरण प्रमाण पत्र, नागरिकता प्रमाण पत्र, किसी भी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी लाइसेंस या सर्टिफिकेट, सरकार या सरकारी संस्था के तहत सेवा या नियुक्ति को प्रमाणिक करने वाला कागजात, बैंक या पोस्ट ऑफिस अकाउंट, जन्म प्रमाण पत्र, राज्य के एजुकेशन बोर्ड या यूनिवर्सिटी के प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, कोई भी एलआईसी पॉलिसी, अदालत के आदेश रिकॉर्ड।

ऊपर बताए गए डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी 24 मार्च, 1971 के बाद का नहीं होना चाहिए। अगर किसी नागरिक के बाद इस तारीख के बाद के कागजात हैं तो वह अपने पिता या दादा के कागजात को दिखा सकता है।

लिस्ट बी के दस्तावेज

जन्म प्रमाण, बोर्ड या विश्वविद्यालय प्रमाण पत्र, मतदाता सूची में नाम, राशन कार्ड , बैंक या एलआईसी या पोस्ट ऑफिस रिकॉर्ड, कानूनी रूप से स्वीकार्य अन्य कोई कागजात, भूमि दस्तावेज, विवाहित महिलाओं के केस में सर्कल अधिकारी या ग्राम पंचायत सचिव की ओर से दिया गया प्रमाण पत्र, लोग लिस्ट बी में बताए गए डॉक्यूमेंट्स को दिखाकर पिता या दादा से संबंध साबित कर सकते हैं।

असम के लोग एनआरसी के फाइनल ड्राफ्ट में अपना नाम चेक के लिए इंतजार करते हुये।

सीएए आर्टिकल 14 व 15(1) का उलंघन

नागरिकता कानून में संशोधन के बाद से ही पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और ये माँग उठ रही है कि 'सरकार शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने वाले इस नए कानून को वापस ले क्योंकि यह संवैधानिक भावना के विपरीत है और भेदभावपूर्ण है।' इस अधिनियम में बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के छह अल्पसंख्यक समुदायों (हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई और सिख) से ताल्लुक रखने वाले लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। विरोध करने वालो का कहना है कि यह नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) आर्टिकल 14 व 15 (1) का उलंघन है।

वहीं गृह मंत्री अमीत शाह ने सदन में इस पर तर्क दिया कि इन तीन देशो के गैर मुस्लिम (हिन्दु, सिख, जैन, पारसी, ईसाई और बौद्ध) नागरिको को जो धार्मिक उत्पीड़न के चलते भारत आये हैं उन्हे नागरिकता दी जायेगी।

अब इस पर सवाल उठता है कि क्या सरकार के पास कोई डाटा है जिससे यह पता चल सके कि कितने लोग घुसपैठिये है और कौन शणार्थी हैं या जो लोग भारत में आये हैं वह धार्मिक उत्पीड़न के चलते हैं या किसी और वजह से। सिर्फ इन तीन देशो (पाकिस्तान, अफगानिस्तान व बांग्लादेश) के ही अल्पसंख्यक नागरिको पर ही केन्द्र सरकार विशेष महत्व क्यों दे रही है। केन्द्र सरकार को श्रीलंका के हिन्दुओं पर हो रहे उत्पीड़न का दर्द नहीं दिखाई दे रहा या फिर तिब्बत से आये बौद्ध नागरिको को क्यों नहीं इसमें शामिल किया गया। कुछ समय पूर्व म्यमार में धार्मिक उत्पीड़न के चलते रोहिंगियों ने देश में शरण ली उस पर बीजेपी के नेताओं ने इन्हे बाहर निकालने की मांग करते हुये कहा था कि ''भारत कोई धर्मशाला नहीं''।

आर्टिकल–14ः समानता का अधिकार

भारत के संविधान में यह कहा गया है कि राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समता से या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 के हिसाब से इसका मतलब यह है कि सरकार भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगी। भारतीय संविधान के भाग–3 में मौजूद समता का अधिकार में आर्टिकल 14 के साथ ही अनुच्छेद–15 जुड़ा है. इसमें कहा गया है, 'राज्य किसी नागरिक के खिलाफ सिर्फ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेद नहीं करेगा।'

विपक्ष का यही कहना है कि नागरिकता संशोधन कानून 2019 धर्म के आधार पर लाया गया है। इसमें एक खास धर्म के लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, जो आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, हालांकि केंद्र सरकार ने इससे इनकार किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून (2019) तीन पड़ोसी देशों में धार्मिक उत्पीड़न के शिकार शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देगा, न कि भारत में किसी की नागरिकता छीनेगा। अमित शाह ने कहा है, 'नए कानून का मतलब यह नहीं है कि सभी शरणार्थियों या अवैध प्रवासियों को अपने आप ही भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। उन्हें भारत की नागरिकता पाने के लिए आवेदन करना होगा जिसे सक्षम प्राधिकरण देखेगा। संबंधित आवेदक को जरूरी मानदंड पूरे होने के बाद ही भारतीय नागरिकता दी जाएगी।'

आर्टिकल–15 ः समता का अधिकार

भारतीय संविधान का आर्टिकल 15 विधि के समक्ष समता के अधिकार बारे में है। अर्थात विधि के लिए सभी नागरिक बराबर हैं और जात पात, धर्म, लिंग के आधार पर नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 में कही गई बातों की शुरुआत आर्टिकल 14 से होती है, जिसमें दो मुख्य बातें कही गई हैं।

1. आर्टिकल 14 में कहा गया है कि विधि के समक्ष समता, सभी नागरिक समान हैं।

2. विधियों के समान संरक्षण की बात भी आर्टिकल 14 में कही गई है। अर्थात कानून की समान सुरक्षा। इसके कई अर्थ हैं, जिसमें एक यह है कि कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं है। किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा।

आर्टिकल 15 समता के अधिकार के बारे में ही हमें आगे बताता है, जो बात आर्टिकल 14 में शुरू होती है, उसे आर्टिकल 15 आगे बढ़ाता है। आर्टिकल 15 समता के अधिकार का विस्तृत विवरण देता है। संविधान सभा का मानना था कि असमानता के खिलाफ स्पष्ट वर्णन करने के लिए आर्टिकल 14 पर्याप्त नहीं होगा, इसलिए सभा ने विधि के समक्ष समता को समझाने के लिए आर्टिकल 14 से 18 तक इसका वर्णन किया।

आर्टिकल 15 (1) के अनुसार किसी भी जाति, वर्ग, लिंग या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। राज्य किसी नागरिक से केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15 का दूसरा उपबंध याने आर्टिकल 15 (2) कहता है कि सार्वजनिक भोजनालयों, दुकानों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश, या

अभी कुछ दिन पहले गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने सीएए को सही ठहराते हुये कहा था कि ''मुस्लिमो के लिए 150 देश है, लेकिन हिन्दुओं के पास केवल भारत''। मुख्यमंत्री रूपानी ने अपने बयान में हिन्दू-मुस्लिम का जिक्र तो कर दिया लेकिन उन्हे बौद्ध और ईसाइयों के बारे में कुछ नहीं कहा, शायद उन्हे पता नहीं कि भारत के पड़ोसी देश जैसे श्रीलंका एवं म्यमार ने अपने देश को बौद्धिस्ट राष्ट्र घोषित किया हुआ है और ईसाइयों के बार में तो कहना ही क्या पूरी दुनिया में ईसाइयों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। तो ऐसे में बीजेपी सरकार क्या करना चाह रही है यह किसी से छिपा नहीं है।

राज्य–निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नानघाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग में कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा। हर नागरिक इनका उपयोग बिना किसी भेदभाव के कर सकता है।

आर्टिकल 15 (3) के अनुसार यदि महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेसल प्रोविजन बनाए जा रहे हैं तो आर्टिकल 15 ऐसा करने से नहीं रोक सकता। जैसे महिला आरक्षण या बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा। यूं तो सभी नागरिक समान हैं लेकिन महिलाओं एवं बाल विकास के लिए उठाए गए विशेष कदम में आर्टिकल 15 बाधा नहीं है।

आर्टिकल 15 (4) के अनुसार राज्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं। अगर वे कमजोर वर्ग के लिए कोई योजना बनाते हैं तो यह आर्टिकल 15 का उल्लंघन नहीं होगा। राज्य सीटों का रिजर्वेशन या फीस में छूट देने जैसे निर्णय ले सकते हैं।

आर्टिकल 15 मौलिक अधिकार भी है और मानव अधिकार भी है। इस तरह हमने देखा कि आर्टिकल 15 भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक के प्रावधानों की अहम कड़ी है, जो समता के अधिकार का वर्णन करता है।

इन राज्यों पर सीएए का सबसे अधिक असर पड़ेगा

सीएबी का सबसे अधिक असर पूर्वोत्तर के सात राज्यों पर पड़ेगा। भारतीय संविधान की छठीं अनुसूची में आने वाले पूर्वोत्तर भारत के कई इलाकों को नागरिकता संशोधन कानून में छूट दी गई है। छठीं अनूसूची में पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम आदि शामिल हैं जहां संविधान के मुताबिक स्वायत्त जिला परिषद हैं जो स्थानीय आदिवासियों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है।

ईगो बचाने के लिए एक देश को जलने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता : चेतन

चेतन भगत ने ट्वीट में लिखा, "यह ध्यान देने का वक्त है. आधिकारिक तौर पर सीएए को किनारे रखिए. बहुत ज्यादा संवादहीनता है. ऐलान कीजिए कि एनआरसी नहीं आएगा, इसे लागू करने की दिक्कतें, इसको लेकर पैदा हुई चिंता और दुरुपयोग की आशंकाओं का मतलब है कि हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। आने वाले बजट पर ध्यान दीजिए। इसका कोई फायदा नहीं है। ईगो बचाने के लिए एक देश को जलने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता।"

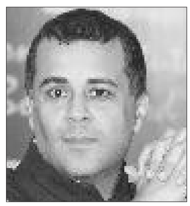

दंगा भड़काते हुए पकड़े गए बीजेपी कार्यकर्ता

नमाजियों वाली टोपी पहनकर कर रहे थे पथराव

असम में एनआरसी करवाने में 16 सौ करोड़ कहा हुआ खर्च : संजय सिंह

एनआरसी करवाने की सरकार की जिद को सनक बताते हुए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा

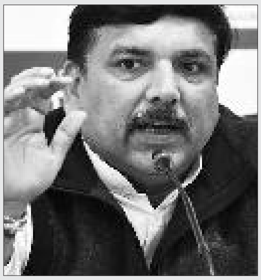

सांसद संजय सिंह ने लिखा– असम में 3 करोड़ लोगों के बीच एनआरसी कराने में 16 सौ करोड़ लगे तो 130 करोड़ लोगों की एनआरसी में 70 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे, अगर भाजपा के मुताबिक 3 करोड़ घुसपैठिया मिले, उनको "डिटेन्शन सेंटर" में रखा गया तो सालाना लगभग 3.65 लाख करोड़ खर्च होगा, निर्माण खर्च अलग, ये सनक नही तो और क्या?

टेलीग्राफ में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता और उसके 5 साथियों को नमाजियों वाली टोपी पहनकर ट्रेनों पर पथराव करने के मामले में गिरफ्तार किया है। अखबार ने पुलिस के हवाले से रिपोर्ट छापी है कि बीजेपी के ये कार्यकर्ता जालीदार टोपी और लुंगी पहन कर ट्रेनों पर पथराव कर रहे थे। स्थानीय निवासियों ने उन्हें चलती ट्रेन पर पत्थर फेंकते हुए देखा और पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।

मुर्शिदाबाद के एसपी मुकेश ने कहा कि पश्चिम बंगाल के राधामाधबतला में पकड़े गए युवक का नाम अभिषेक सरकार है, वह 21 साल का है और बीजेपी का सदस्य है। पकड़े जाने के बाद युवकों ने खुद को बचाने के लिए कहा कि उन्होंने टोपी और लुंगी वीडियो शूट करने के लिए पहनी थीं, जिसे वे अपने यूट्यूब चैनल पर डालना चाहते थे। जबकि पड़ताल करने पर पता चला कि उनका कोई यूट्यूब चैनल नहीं है।

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक रैली को संबोधित करते हुए ये दावा किया था कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के लिए नमाजियों वाली टोपी खरीद रही है। मुसलमानों को बदनाम करने के लिए इस टोपी को पहनकर बीजेपी के लोग हिंसा को अंजाम दे रहे हैं। अब बीजेपी कार्यकर्ता की गिरफ्तारी ने ममता बनर्जी के इस दावे की तस्दीक कर दी है।

मैं वास्तव में बहुत शर्मिंदा हूं

मारिको कंपनी के मालिक किशोर मारीवाला को थाईलैंड में शर्मिंदा होना पड़ा। उन्होंने फेसबुक पोस्ट लिखकर थाईलैंड में हुई घटना को शेयर किया। उन्होंने बताया कि देश में जो माहौल बना है, उसके बाद थाईलैंड में हिन्दुओं की छवि खराब हो रही है। 4 जनवरी को 84 वर्षीय किशोर मारीवाला थाईलैंड पहुंचे।

उन्होंने 5 जनवरी को फेसबुक पोस्ट पर लिखा, ''मैं शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं। मैं छुट्टी मनाने के लिए फुकेट, थाईलैंड आया हुआ हूं. मैंने एक हफ्ते पहले ही यॉट (एक कैप्टन के साथ) बुक की थी। कल मैं कंपनी के ऑफिस में पहुंचा। मैं देखना चाह रहा था कि सारी व्यवस्था है कि नहीं। रिसेप्शन में पहुंचा। वहां मुझसे सारी डिटेल्स ली गईं।

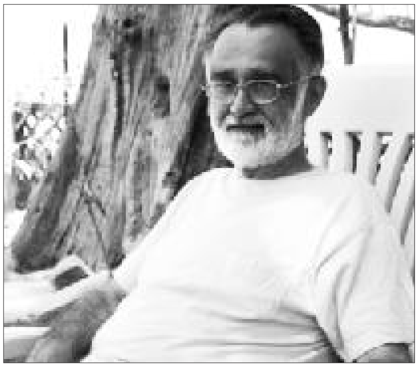

फिर पूछा, सर, क्या आप इंडिया से हैं? क्या आप हिन्दू हैं? मैंने हां कहते हुए पूछा, आप मुझसे ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हैं?''

मारीवाला ने आगे लिखा, ''लड़की ने अपने बॉस और मैनेजर को बुलाया और थाई भाषा में बात करने लगे। मैनेजर मेरे पास आया और बोला, सर, नौका तो है लेकिन हमारे पास देने के लिए सिर्फ एक स्टाफ है और वह मुस्लिम है. क्या आप उसके साथ जाना पसंद करेंगे? क्या आप बुरा नहीं मानेंगे? मैं सुनकर हैरान रह गया। मैंने पूछा– आप यह क्यों कह रहे हैं? मैं क्यों बुरा मानूंगा? जिस पर मैनेजर ने कहा, हमने अखबारों में पढ़ा है कि हिन्दू अपने इर्द–गिर्द मुसलमानों को नहीं देखना चाहते हैं। इसीलिए हम इस बात को लेकर परेशान थे। मेरे सामने कोई शब्द नहीं थे। मैं खुद से शर्मिंदा था. मैंने उसे समझाया– हिंदू ऐसे बिल्कुल नहीं हैं, वे सभी को पसंद करते हैं. क्या विदेशों में वहां आम लोगों के बीच हमारी छवि ऐसी बनी रही है? मैं वास्तव में बहुत शर्मिंदा हूं।''

हिन्दुओं पर अत्याचार बढ़ाने वाला हिन्दू विरोधी कानून

देहरादून। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 धर्म के आधार पर अवैध घुसपैठियों को उनकी भारत में घुसपैठ की तिथि से नागरिकता के लिये प्रावधान करने वाला काला कानून है। यह असंवैधानिक व मूल अधिकार हनन करने वाला कानून भारत की सर्वधर्म समभाव की विश्व छवि को खराब तो करेगा ही साथ ही विदेशों में हिन्दुओं पर अत्याचार बढ़ाने वाला हिन्दू विरोधी कानून भी है। उक्त उदगार प्रतिष्ठित समाज सेवी संस्था मौलाना अबुल कलाम आजाद अल्पसंख्यक कल्याण समिति (माकाक्स) के केन्द्रीय अध्यक्ष तथा कानून के जानकर नदीम उद्दीन (एडवोकेट) ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके प्रभावों पर जानकारी देते हुये व्यक्त किये।

नदीम ने बताया कि 6 धाराओं के इस कानून में धारा 2 से अवैध प्रवासी जिसे साधारण शब्दों में अवैध घुसपैठिया कहा जा सकता है, की परिभाषा में स्पष्ट किया है कि 31 दिसम्बर 2014 से पूर्व भारत में प्रवेश करने वाले अफगानिस्तान, बांग्लादेश तथा पाकिस्तान के हिन्दू, सिक्ख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय के व्यक्तियों को अवैध प्रवासी नहीं माना जायेगा। उल्लेखनीय है कि भारत में अवैध प्रवासी नागरिकता का पात्र नहीं है। इससे यह घुसपैठिये नागरिकता के पात्र हो जायेंगे। इस अधिनियम में कहीं भी शरणार्थी तथा धर्म के आधार पर उत्पीड़न का उल्लेख नहीं किया गया है जैसा कि प्रचारित किया जा रहा है। यहां बता दें कि शरणार्थियों तथा वैध रूप से भारत में रह रहे विदेशियों के लिये पहले से ही नागरिकता का प्रावधान है जिसके लिये इस कानून की आवश्यकता ही नहीं है।

उन्होंने बताया कि इस कानून से किसी भी व्यक्ति को स्वयं नागरिकता नहीं मिलेगी बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश का घुसपैठिया बताते हुये उसे आवेदन करना पड़ेगा तथा नागरिकता की शर्ते पूर्ण करने व उसका आवेदन अधिकारियों द्वारा स्वीकार करने पर ही नागरिकता मिलेगी। इस कानून से पहले भी लम्बी अवधि के वीजा धारक विभिन्न पात्र शरणार्थी अधिकारियों के नागरिकता के लिये चक्कर लगा रहे है और उन्हें नागरिकता नहीं मिल पा रही है। इस लाइन में लाखों लोग और बढ़ जायेंगे। श्री नदीम के अनुसार इस कानून से 9 प्रतिशत से अधिक हिन्दू आबादी वाले बंग्लादेश, 2 प्रतिशत आबादी वाले पाकिस्तान तथा लगभग 1 प्रतिशत हिन्दू आबादी वाले अफगानिस्तान में हिन्दुओं का उत्पीड़न बढ़ जायेगा और वहां के कट्टवादी व अलगावादी लोग उन्हें भारत जाकर रहने को कहने लगेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य देशों में हिन्दुओं के प्रति उत्पीड़न व नफरत बढ़ने तथा भारत की धार्मिक सदभाव व प्रेम की संस्कृति तथा छवि पर प्रतिकूल असर पढ़ने की भी संभावनायें रहेगी।

बंग्लादेश, पाकिस्तान व अफगानिस्तान के सभी गैरमुस्लिम नागरिकों का अपनी मातृभूमि व घर व कारोबार छोड़कर भारत आना न तो संभव है और न ही इतनी बड़ी आबादी को भारत में नागरिकता ही दी जा सकती है। जब भारत के विभिन्न प्रांतों के लोगों को दूसरे प्रांत के लोगों को अपनाने में ही कठिनाई आती है तो वह इन विदेशी घुसपैठियों को कैसे अपनाएंगे। श्री नदीम के अनुसार इस कानून का शांतिपूर्ण विरोध बड़ी संख्या में विदेशी घुसैपैठियों को नागरिकता का प्रावधान करने तथा उसमें भी धर्म के आधार पर भेदभाव करने के कारण होना चाहिये। आज सरकार ने धर्म के आधार पर भेदभाव करने वाला कानून बनाया है, कल जाति के आधार पर भेदभाव करेगी, परसों किसी अन्य आधार पर। इससे तो देश की आजादी तथा लोकतंत्र ही खतरे में पड़ जायेगा।

पूरे भारत को एनआरसी के खिलाफ सत्याग्रह करना चाहिए और गांधी-हाजी हबीब से मांफी मांगनी चाहिए

कभी इसका भी हिसाब कीजिए कि असम के आम आदमी का कितना खर्च हुआ। एक एक सर्टिफिकेट बनाने में 5000 से 15000 तक खर्च हुए।

असम की आबादी साढ़े तीन करोड़ ही है। नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) के नाम राज्य ने 1600 करोड़ फूंक दिए। राज्य के करीब 4 साल बर्बाद हुए। 2019 के अगस्त में जब अंतिम सूची आई तो मात्र 19 लाख लोग उसमें नहीं आ सके। इनमें से भी 14 लाख हिन्दू हैं। बाकी 5 लाख के भी कुछ रिश्तेदार भारतीय हैं और कुछ नहीं। इन सबको फोरेन ट्रिब्यूनल में जाने का मौका मिलेगा। उसके बाद तय होगा कि आप भारत के नागरिक हैं या नहीं। वहां भी केस को पूरा होने में छह महीने से साल भर कर समय लग सकता है।

हम सरकार का खर्च जोड़ते हैं। कभी इसका भी हिसाब कीजिए कि असम के आम आदमी का कितना खर्च हुआ। एक एक सर्टिफिकेट बनाने में 5000 से 15000 तक खर्च हुए। बिहार और यूपी से गए लोगों के वंशज वापस अपने गांवों में आकर रिश्वत देकर सर्टिफिकेट बनवाते रहे। ट्रिब्यूनल के लिए वकीलों की फीस भी जोड़ लें। साढ़े तीन करोड़ लोग चाहे वो हिन्दू थे या मुस्लिम, नेशनल रजिस्टर के लिए अपनी जेब से 5 से 50 हजार तक खर्च्च कर रहे थे। किसी की मामले में एक लाख रुपये तक। अब अगर भारत भर में हुआ तो सोच लें कि आप सब पर नोटबंदी की तरह एक और बोगस योजना थोपी जाने वाली है।

असम में इतनी बड़ी कवायद का नतीजा एक तरह से जीरो निकला। दशकों से नेता हिन्दी प्रदेश के लोगों पर यह झूठ थोपते रहे कि एक करोड़ घुसपैठिया आ गए हैं। किसी ने 40 लाख कहा तो किसी ने कहा कि सारा भारत घुसपैठियों से भर गया है। यह धारणा इतनी मजबूत हो गई कि नेशनल रजिस्टर की नौबत आ गई। राजीव गांधी सरकार और असम के छात्र आंदोलन के बीच जो असम समझौता हुआ था, उसमें भी यह बात थी। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि नेशनल रजिस्टर का काम शुरू हो। असम गण परिषद भी घुसपैठियों को निकालने की राजनीति करती थी। लेकिन उसने हिन्दू घुसपैठिया या मुस्लिम घुसपैठिया में फर्क नहीं किया। फर्क अब किया जा रहा है।

संदिग्ध नागरिकों की जो संख्या निकली है वो उतनी तो नहीं है जो हमारे नेता अपने भाषणों में लोगों पर थोपते हैं। करोड़ों

"पूरे भारत में एन आर सी की बात हो रही है। जाहिर है पूरे भारत को लंबे समय के लिए एक और हिन्दू मुस्लिम डिबेट में फंसाया जा रहा है"

घुसपैठियों का भूत दिखाया गया जबकि मिले 3 से 5 लाख वो भी अभी साबित नहीं है। इसके बाद भी अब पूरे भारत में एन आर सी की बात हो रही है। जाहिर है पूरे भारत को लंबे समय के लिए एक और हिन्दू मुस्लिम डिबेट में फंसाया जा रहा है। गृहमंत्री को भरोसा है कि सिर्फ मुसलमान को छोड़ कर हिन्दू, ईसाई, सिख, जैन पारसी और बोद्ध को नागरिकता देने से विपक्ष जब विरोध करेगा तो लोग अपने आप समझ जाएंगे कि मुसलमानों को नागरिकता देने की वकालत हो रही है। और यह उनके काम आएगी।

एक सवाल है। इस सूची में ईसाई क्यों हैं? ईसाई हैं तो मुसलमान क्यों नहीं? क्या अंतर्राष्ट्रीय छवि या दबाव के डर से ईसाई को शामिल किया गया है? संघ परिवार अपने शुरूआती दिनों में ईसाई मिशनरियों पर धर्मांतरण के आरोप लगाता था। ओडिसा में ग्राहम स्टेंस को जला कर मार दिया गया था। अब धर्मांतरण की बात क्यों नहीं हो रही है? फिर मुसलमान को हटा कर नागरिकता के नियम को धर्म के आधार पर क्यों बांटा जा रहा है? आपको लगता है यह सही है तो भारत के इतिहास के इस पन्ने को पलट लीजिए।

20 अगस्त 1906 को दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल शहर में नियम बनता है कि पुरानी परमिट रद्द की जाएगी। एशियाई मूल को लोगों को रजिस्टार के दफ्तर में जाकर नया रजिस्ट्रेशन कराना होगा और अंगूठे के निशान देने होंगे। यह फैसला भारत और चीन के लोगों को प्रभावित करता था। नया परमिट नहीं दिखाने पर जेल का प्रावधान था। गांधी जी ने मानने से इंकार कर दिया।

11 सितंबर 1906 को जोहानेसबर्ग के पुराने एम्पायर थियेटर में 3000 भारतीयों की सभा होती है। गांधी जी के साथ गुजरात के व्यापारी सेठ हाजी हबीब भी थे। उन्होंने कह दिया कि हम सभी ईश्वर की शपथ लेंगे कि इस नियम को नहीं मानेंगे। गांधी जी स्तब्ध हो गए। उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते। ईश्वर की शपथ लेकर तोड़ नहीं सकते। हमें ठीक से विचार करना चाहिए। सबने सोच लिया और तय किया कि नए परमिट को नहीं मानेंगे। उस दिन सत्याग्रह का जन्म हुआ।

आज उसी सेठ हाजी हबीब का भारत बदल गया है। उसमें अब नैतिक बल नहीं रहा कि वह ईश्वर की शपथ लेकर हाजी हबीब के लिए खड़ा हो जाए। बस सोचिए कि हिन्दू मुस्लिम की राजनीति आपको कहां धकेल रही है। रजिस्टर की लाइन में खड़ा कर आपसे भी नागरिकता का प्रमाण मांग रही है। कायदे से तो पूरे भारत को इस एन आर सी के खिलाफ सत्याग्रह करना चाहिए और एन आर सी जैसे ख्याल के लिए गांधी और सेठ हाजी हबीब से मांफी मांगनी चाहिए।

एनआरसी और सीएए को लेकर कुछ ज्वलंत सवाल

1. 130 करोड़ लोगों की एनआरसी में लगभग 70 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे, क्या हमारे देश की आर्थिक स्थिति इसकी इजाजत देती है?
2. असम में जो 19 लाख एनआरसी से बाहर हुये हैं उनका सरकार किया करेगी या उन्हे कब देश से बाहर करेगी, जिसका सरकार दावा करती थी?
3. क्या सरकार के पास कोई डाटा है कि हमारे देश में कितने लोग घुसपैठिये हैं और कितने लोग शाणार्थी?
4. आखिर सरकार किसी आधार पर यह निर्णय लेगी कि कौन धार्मिक प्रताड़ना की वजह से हिन्दुस्तान आये हैं?
5. सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान व बाग्लादेश के अल्पसंख्यको को ही क्यो नागरिकता दी जायेगी?
6. सरकार श्रीलंका में प्रताड़ीत तमील हिन्दुओं को सीएए के अंतर्गत क्यों नहीं ला रही?
7. क्या सरकार जानबुझकर ऐसे मुददे उठा रही है जिससे लोगो देश के आर्थिक हालात, बेरोजगारी, महांगाई आदि जैसे मुद्दो पर सरकार से सवाल न पूछे?

दून को स्मार्ट सिटी बनाने की पहल

अपराधी अब कैमरे की कैद में रहेंगे

अब तैयारी हो रही है दून को स्मार्ट सिटी बनाने की, जो कि फरवरी आखिरी तक शहर को 250 से 300 तक स्मार्ट आंखें मिल जायेगी, जो स्मार्ट सिटी योजना के तहत लगाए जा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा हैं यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरे होंगे और इन कैमरों की नजर से शायद ही कोई बच पाए। यह कैमरे पूरी राजधानी में लगाए जाएंगे। वैसे तो कुछ कैमरे लगाए जा चुके हैं और बाकी कैमरे फरवरी तक लगा दिए जाएंगे। इन कैमरों से अपराधियों की पहचान होगी। जिस तरह से कुछ सालों में अपराध का ग्राफ बढ़ा है, उससे पुलिस प्रशासन की सांसें फूल गई है तथा इन कैमरों से पुलिस प्रशासन को भी बहुत मदद मिलेगी और अपराध में अंकुश लगेगा।

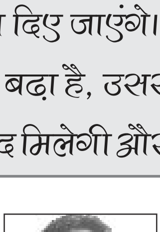

अशोक रावत
गढवाल प्रभारी

अब अतीत का वह खूबसूरत उत्तराखंड कहीं नजर नहीं आता, भले ही कहा जा सकता है कि सड़के बनी, भवन बने, लोगों को थोड़ा बहुत रोजगार मिला, विकास हुआ, मगर संस्कृति, सभ्यता, शांति, पर्यावरण और नैतिकता, चरित्रता, इमानदारी की भावना का जिस तरह से विनाश हुआ, उसे कोई न देख पाया न महसूस कर पाया। कम से कम ऐसी उन्नति का समर्थन तो कोई नहीं करना चाहेगा, जो चोरी, डकैती, हत्या, भ्रष्टाचार, नैतिकता, चरित्रता एवं निम्न स्तर की राजनीति की आधारशिला पर खड़ा हो और हमारी संस्कृति, नैतिकता, चरित्रता, रीति–रिवाजों, परंपराओं को नष्ट कर रहा हो। उत्तराखंड को स्विट्जरलैंड बनाने की होड़ लगी हुई है, हमारी संस्कृति शरीर से

"किसी ने सही कहा है क्या सोचकर उतरे थे हम राज्य की लड़ाई में गैरों से तब जीते, अपनों से अब हारे लड़ाई में"

जैसे कपड़े उतार कर हमें नंगा कर रही है। वह तमाम कार्य कर रही है, जो हमें हर स्तर पर गिरा तो सकते हैं, उठा नहीं सकते।

यह इसी से स्पष्ट हो जाता है कि सड़कें चौड़ी सुंदर तो बन गई है। कारे, स्कूटर, मोटरसाइकिल लगभग हर एक के पास है, लेकिन सड़क पर चलने की तहजीब किसी को नहीं आई। विकास, उन्नति की परिभाषा आखिर क्या है? इस पर गंभीरता से मंथन करने की आवश्यकता है। क्या आलीशान कोठियां, होटल, कॉलेज, तकनीकी शिक्षण संस्थान बना देना, चौड़ी सड़के बना देना, बड़े–बड़े आधुनिक मशीनों से लैस चिकित्सालय बना देना जहां सिर्फ नेता, अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, चिकित्सा का लाभ उठा सके, गरीब व मध्यम वर्ग जहां जाने की सोच भी न सके। वायुयानो के लिए आकर्षक हवाई अड्डे बनाना, जिनमे में अधिकतर नेता, सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी उसमें सरकारी खर्चे पर यात्रा कर सकें। इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खोलना जहां सीट बिकती है। लाखों रुपए की फीस जो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो क्या यही विकास है? ऐसा विकास जो आम आदमी तक ना पहुंच सके क्या सही श्रेणी में आता है? राज्य उस व्यक्ति के लिए नहीं बना जिसने एक आदर्श राज्य की कल्पना कर सड़कों पर आंदोलन किया, लड़ाई लड़ी और इमानदारी से बिना स्वार्थ के अपनी भागीदारी निभाई थी। राज्य बनने के 19 वर्षों में माफिया को छोड़ दे, नेताओं को छोड़ दें, चमचों को छोड़ दे तो आम आदमी के हाथ सिर्फ निराशा लगी है। किसी संस्कृति का निर्माण कुछ वर्षों में नहीं होता, उसके निर्माण में हजारों वर्ष का समय लगता है। लोगों का निःस्वार्थ भाव त्याग, तपस्या, आदर्श, उच्च कोटि का चरित्र, बलिदान होता है, तब जाकर कहीं कोई संस्कृति विकसित होती है, पर हम उनका महत्व नहीं समझ सके।

आज हमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि हम उत्तर प्रदेश, बिहार को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। उत्तराखंड स्थापना दिवस पर आज भाषण झाड़ने की आवश्यकता नहीं है, किसी ने सही कहा है क्या सोचकर उतरे थे हम राज्य की लड़ाई में गैरों से तब जीते, अपनों से अब हारे लड़ाई में।

उत्तराखण्ड शासन

कृषि निदेशालय उत्तराखंड देहरादून

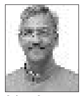

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत जी
मा0 मुख्यमंत्री

परंपरागत कृषि विकास योजना से जैविक कृषि क्षेत्र को मिल रही है गति

वर्ष 2015–16 से भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय सम्पोषणीय कृषि मिशन के अंतर्गत परम्परागत कृषि विकास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना 90 प्रतिशत केंद्रांश एवं 10 प्रतिशत राज्यांश पर संचालित है। वर्ष 2015–16 से वर्ष 2017–18 तक योजना 585 कलस्टर में संचालित की गयी। उत्तराखंड प्रदेश को जैविक प्रदेश बनाने हेतु के उद्देश्य से योजना का विस्तार करते हुए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018–19 में 3900 नए समूहों/कलस्टर स्वीकृत किए गए, जिनका क्रियान्वयन वर्तमान में किया जा रहा है। एक कलस्टर के अंतर्गत 20 है0 क्षेत्रफल एवं 50 कृषक आच्छादित किए जा रहे हैं, इसमें 78000 है0 क्षेत्रफल जैविक कृषि के अंतर्गत आच्छादित हो रहा है। योजना का क्रियान्वयन योजनान्तर्गत नियुक्त लीड रिसोर्स पर्सन (LRP) के सहयोग से किया जा रहा है। पांच कृषक समूह से एक लीड रिसोर्स पर्सन (LRP) का चयन कर कार्यमदो का संचालन किया जा रहा है। प्रत्येक जनपद में योजना के क्रियान्वयन हेतु मुख्य कृषि अधिकारी एवं जिला उद्यान अधिकारी को उत्तरदाई बनाया गया है।

स्थानीय जलवायु परिस्थिति एवं विपणन को देखते हुए विभिन्न प्रकार के कलस्टर चयनित कर उनमें कार्य सम्पादित किया जा रहा है। परम्परागत कृषि विकास योजना के अन्तर्गत परम्परागत कृषि फसलों जैसे धान्य फसलें मंडुवा, झंगोरा, चीना, दलहनी फसलों जैसे तोर, उड़द, नौरंगी, मसूर, गहत, कुल्थी तथा तिलहनी फसलों सोयाबीन, भट्ट, तिल, तोरिया/सरसों आदि की जैविक खेती में परम्परागत तकनीकी एवं आधुनिक कृषि तकनीकी का यथा संभव समावेश कर इन फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करते हुए कृषकों की आय बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। योजना का मुख्य उद्देश्य कलस्टर एप्रोच के आधार पर चयनित जैविक ग्रामों में पी0जी0एस0 सर्टिफिकेशन के अन्तर्गत जैविक कृषि का प्रोत्साहित किया जाना है।

वर्तमान में योजनान्तर्गत परम्परागत फसलों के 2555, फल/सब्जियों/फूलों के 1241, सगन्ध पौध केंद्र 45 तथा रेशम के 59 कलस्टर संचालित हैं। योजना के क्रियान्वयन हेतु 10 सपोर्ट एजेन्सी एवं 9 रिजनल काउन्सिल का चयन किया गया है। जैविक खेती पर कृषक प्रशिक्षण एवं कृषकों को एक्सपोजर भ्रमण कार्यक्रम कराया जा रहा है तथा पी0जी0एस0 प्रमाणीकरण, जैव निवेशों के वितरण, जैविक उत्पादों का विपणन, ब्रांड ब्यूल्डिंग, मेले, प्रदर्शनी, प्रचार–प्रसार एवं स्थानीय मेलों तथा राष्ट्रीय मेलों में प्रतिभाग हेतु योजना की नई गाईड लाईन के अनुसार कृषिकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जा रही है।

योजना के संचालन से जहां जैविक कृषि के क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है वहीं कृषकों को अपने उत्पादों का उचित मूल्य भी प्राप्त हो रहा है। उत्तराखंड प्रदेश के उत्पाद जलवायु विशेष के कारण पोष्टिक एवं औषधीय उपयोग के भी हैं। परम्परागत कृषि के अन्तर्गत पी0जी0एस0 प्रमाणीकरण से इनका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। योजना जहां कृषकों के आय बढ़ाने में सहायक हैं वही पर्वतीय क्षेत्रों में जहां पर चकबन्दी नहीं है कलस्टर आधारित कृषि को प्रोत्साहित कर रही है।

सरकार के लिए चुनौतियों का अम्बार रहेगा 2020

सुशील कुमार सिंह
(शिक्षाविद्, लेखक, स्तम्भकार, मोटिवेशनल स्पीकर)
निदेशक,
प्रयास आईएएस स्टडी सर्किल
देहरादून।

बेशक मोदी सरकार पुराने डिजाइन से बाहर निकल गई हो पर दावे और वादे का परिपूर्ण होना अभी दूर की कौड़ी है। नये साल के आगाज पर सरकार भी कई मामलों में संकल्पबद्ध हो रही होगी, मगर बीते साल की चुनौतियां उसे कहीं ना कहीं चपेट में लिए हुए हैं। मसलन नागरिकता संशोधन विधेयक, एनआरसी, एनपीआर समेत महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी और प्रदेशों में दल को मिल रही हार। सुस्त अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ाने में सरकार कई प्रयोगों के बावजूद स्थिति में कोई खास सुधार नहीं कर पाई है। जाहिर है नये साल के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। महंगाई दर की राह में सबसे बड़ी बाधा है जाहिर है जब क्रय शक्ति घटती है तो खपत भी घटती है और इसका नकारात्मक असर जीडीपी पर पड़ता है। महंगाई को पटरी पर लाना और बीते 6 साल के मुकाबले निम्न स्तर पर पहुंच चुकी 4.5 फीसदी जीडीपी को 7 या 8 फीसदी के इर्द–गिर्द लाना साल 2020 में सरकार के लिए पहली 2–3 चुनौतियों में एक रहेगी।

गौरतलब है कि 5 ट्रिलियन डॉलर की व्यवस्था के लिए 8 प्रतिशत जीडीपी की आवश्यकता है। सरकार ने अर्थव्यवस्था का जो भारी–भरकम स्वरूप बनाने का मन बनाया है, मौजूदा जीडीपी को देखते हुए कह सकते हैं कि यह आसान राह नहीं है। अगर भारत को बदलाव की चुनौती का मुकाबला करना है तो केवल सामान्य विकास से काम

नहीं चलेगा। इसके लिए बुनियादी बदलाव की जरूरत पड़ेगी, जिसकी पहली आवश्यकता जीडीपी में बढ़ोतरी ही है। साल 2024 तक 5 डॉलर की अर्थव्यवस्था करने का इरादा कहीं कागजो तक ना रह जाये इसके लिए कृषि, विनिर्माण, पूंजी, निवेश आदि को लेकर लंबी छलांग लगानी होगी। गौरतलब है कि वर्तमान में जीडीपी खराब अवस्था में है जबकि बीते 5 जुलाई के बजट में लक्ष्य 7 फीसदी रखा गया था। बढ़ता राजकोषीय घाटा भी अब सरकार के बूते से बाहर है। हालांकि सरकार का इस मामले में कई वर्षों तक खराब प्रदर्शन नहीं रहा है, पर स्थिति को देखते हुए राजकोषीय घाटा भी लक्ष्मण रेखा लांघ रहा है। यह घाटा 3.3 फीसदी से अब आगे की ओर जा रहा है, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए आगामी वर्ष में बड़ी चुनौती रहेगा।

अर्थव्यवस्था में सुस्ती की वजह से कर संग्रह घटा है और चालू वित्त वर्ष में घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 3.4 प्रतिशत तक रखने का लक्ष्य है। हालांकि आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह लक्ष्य भी किसी चुनौती से कम नहीं। गौरतलब है कि बढ़ता राजकोषीय घाटा अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित करता है, जिसके चलते ब्याज दरों के साथ महंगाई बढ़ती है। यही कारण है कि पिछली 5 समीक्षाओं में रिजर्व बैंक ने 5 बार रेपो रेट में कमी करते हुए बीते फरवरी से अब तक 1.35 फीसदी की कटौती कर चुका है। जिसके चलते बैंकों को ब्याज दर कम करने का दबाव बनाया। इतना ही नहीं अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कटौती की और भी संभावना है जो कहीं ना कहीं इसका निचला स्तर होगा। जिस तर्ज पर आरबीआई ने रेपो दर को लगातार कम करता रहा उसे पुनः वापसी करना भी नये साल में एक काम रहेगा। आरबीआई की यह चिंता रही है कि आर्थिक सुशासन को कैसे पटरी पर दौड़ाया जाये। इसी के चलते यह लगातार रेपो दर में कटौती करता रहा। सरकार ने भी सितंबर में कॉरपोरेट टैक्स को 10 फीसदी घटाकर आर्थिक सुस्ती को तंदुरुस्ती देने की कोशिश की। साल 2020 में जो भी चुनौती रहेगी कि कारपोरेट टैक्स कैसे बड़े और आरबीआई द्वारा जो कदम उठाये गए उसका लाभ सीधे जनता को कैसे मिले, ताकि देश आर्थिक सुशासन की राह पर चल पाये। निजी निवेश को आकर्षित करना सरकार की चुनौती बनी

✦ रोजगार के स्तर का ऊपर न उठ पाना साथ ही महंगाई का बेकाबू होना आर्थिक समस्या को बढ़ा दिया है

रहेगी। वित्त वर्ष 2015 में निजी निवेश की दर 30.1 फीसदी थी जो 2019 में 28.9 प्रतिशत ही रही। आंकड़ों को तवज्जो दें तो निजी व सरकारी निवेश बीते 14 साल के न्यूनतम स्तर पर है जिसे बढ़ाना नए साल में एक नई चुनौती रहेगी।

अर्थव्यवस्था की गति बरकरार रखने और रोजगार के मोर्चे पर खरे उतरने की चुनौती सरकार के लिए पुरानी बात है मगर यह पुरानी कहानी नए साल में पीछा नहीं छोड़ेगी। बीते समय में देश भर में छोटी कंपनियां कुछ अधिक ही प्रभावित हुई है और बड़ी कम्पनियों में भी नौकरी के अवसर घटे हैं। इतना ही नहीं सरकारी नौकरियां भी समय के साथ सिमट रहीं है। श्रम–बल में बेरोजगारी की दर बीते कई सालों से लगातार बढ़त लेता रहा है और बेरोजगारी दर 6.1 फीसद पर चली गई जो 45 साल का उच्चतम स्तर था। आगामी वर्ष में इस आरोप से मुक्त होने के लिए सरकार को भी एड़ी–चोटी का जोर लगाना होगा। गौरतलब है कि साल 2027 तक भारत सर्वाधिक श्रम–बल बाल देश हो जाएगा और इसकी खपत के लिए बड़े नियोजन की दरकार होगी। अनुमान तो यह भी है कि साल 2022 तक 24 सेक्टरों में 11 करोड़ अतिरिक्त मानव संसाधन की जरूरत होगी। खाद्य कीमतों में तेजी के चलते मूल्य आधारित महंगाई बीते नवंबर में बढ़कर 0.58 फीसद पर पहुंच गई जो कि अक्टूबर में 0.16 थी।

सब्जी और दाल समेत कई वस्तुओं की कीमत बढ़ने से खुदरा महंगाई दर 5.54 प्रतिशत पर चली गयी है। एक और उत्पादन स्तर का लगातार गिरना, रोजगार के स्तर का ऊपर न उठ पाना साथ ही महंगाई का बेकाबू होना आर्थिक समस्या को बढ़ा दिया है। साल 2020 इस चुनौती से दो–चार होगा। किसानों की आय दोगुनी करने का जो लक्ष्य सरकार ने तय किया है समय हालांकि 2022 है पर इस चक्र में 2020 भी रहेगा। सर्वाधिक उत्पादकता वाले इस क्षेत्र पर देश की लगभग 58 प्रतिशत जनसंख्या निर्भर करती है। कृषि का आधुनिकीकरण नहीं होना और परम्परागत पद्धतियों में अब किसानों की आर्थिक अवस्था और व्यवस्था को उथल–पुथल कर दिया है। हालांकि न्यूनतम समर्थन मूल्य में हेरफेर कर सरकार राहत की बात करती है पर स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करने की चुनौती पहले भी रही है और आगे भी रहेगी। मोदी सरकार ने अपनी दूसरी पारी में ताबड़तोड़ निर्णय लिए मसलन जम्मू कश्मीर से 370 का खात्मा, अयोध्या विवाद का सर्वोच्च न्यायालय का समुचित हल निकालना देखा जा सकता है। हालांकि इसी दरमियान हरियाणा में सरकार का बहुमत से जीत न दर्ज करना और महाराष्ट्र में सियासी क्षितिज से जमीन पर आना ताजी सियासत का एक ऐसा नमूना था। जिसका नतीजा झारखंड की हार ने कद को कमजोर कर दिया।

वर्ष 2020 में जहां दिल्ली और बिहार का चुनावी भंवर भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती है, वहीं असम, गोवा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात समेत कई प्रांत सरकार की साख को चुनौती देंगे। मोदी सरकार का सियासी नक्शा भारत से सत्ताधारी के तौर पर राज्यों में जिस तरह सिमट रहा है, जाहिर है 2020 के चुनाव चुनौती रहेंगे। सुशासन की कक्षा में चक्कर लगाने वाली मोदी सरकार इसमें कोई दुविधा नहीं कि दर्जनों असुविधाओं से घिरी हुई है जिसके चलते जो जादू सर चढ़कर बोलता था अब बात वैसे ही नहीं दिखती। अर्थव्यवस्था पर विनिवेश की परत चढ़ाना, लोक विकास की कुंजी सुशासन को समतल ना कर पाना, 5 ट्रिलियन डॉलर वाली अर्थव्यवस्था को जो 8 फीसदी की जीडीपी चाहिए वहां कमतर रहना और तमाम प्रयासों के बावजूद उत्पादन, महंगाई और बेरोजगारी के साथ कई मुद्दे पटल पर व्यवस्थित ना हो पाना 2019 में चुनौती बनी रहेगी। जिसका अक्स 2020 में भी कायम रहेगा। इतना ही नहीं नागरिकता कानून, एनआरसी और एनपीआर को लेकर देश ने बन रहा माहौल को भी साल 2020 में अपने अनुरूप करना सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रहेगा।

सीएए के समर्थन में भाजपाइयों ने निकाली रैली

मसूरी विधानसभा क्षेत्र में सीएए के समर्थन में भाजपाइयों ने रैली निकाली, रैली में कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। रैली आरटीओ कार्यालय से शुरु होकर हाथीबड़कला पुलिस चौकी पर समाप्त हुई। रैली मसूरी विधायक गणेश जोशी के नेतृत्व में निकाली गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रुप में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री अनिल गोयल उपस्थित रहे।

घर घर जाकर सीएए के पक्ष में जन जागरण अभियान चलाया जाए

रैली की समाप्ति पर रैली को सम्बोधित करते हुए मसूरी विधायक गणेश जोशी ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं बांग्लादेश में रहने वाले हिन्दु, जैन, इसाईयों, को सम्मान से जीने का अवसर प्रदान किया है इसके लिए आप दोनों का जितना साधुवाद दिया जाये उतना कम है। रैली को सम्बोधित करते हुए गणेश जोशी ने कहा कि ननकाना साहिब में हाल ही में हुई घटना से सिद्व हुआ है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ हमेशा से अत्याचार होता आ रहा है। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेश पार्टी जिसको जनता ने नकार दिया है, इसके आढ में लोगों को बरगला, फुसलाकर अपना स्वार्थ सिद्व करना चाहती है लेकिन देश की जनता इसके बहकावे में आने वाली नहीं है आज जिस प्रकार का समर्थन सीएए को पूरे देश में मिल रहा है।

वह इस बात का प्रतिक है कि आज जनता सीएए के पक्ष में है। इस अवसर पर लोगों को सम्बोधित करते हुए प्रदेश महामंत्री अनिल गोयल ने कहा कि पार्टी का कोई भी कार्यक्रम हो मसूरी विधानसभा की उसमें अग्रणी भूमिका रहती है और आज की भारी संख्या में उमडी भीड इस बात का प्रमाण है। साथ ही उन्होने आह्वान किया कि घर घर जाकर सीएए के पक्ष में जन जागरण अभियान चलाया जाए व लोगों को इसकी जानकारी दें।

नागरिकता संशोधन कानून

स्वयं सड़क पर उतरे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष

"विपक्ष अपनी हताशा व निराशा के चलते भोले भाले नागरिकों को गुमराह कर रहा"

नागरिकता संशोधन कानून के संबंध में भ्रांतियों को दूर करने को लोगों को पत्रक वितरित करते भाजपा प्रदेश अजय भट्ट।

भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट आज स्वयं यमुना कॉलोनी कुमार मंडी क्षेत्र में नागरिकता संशोधन कानून के संबंध में भ्रांतियों को दूर करने हेतु स्वयं सड़क पर उतरे। क्षेत्र में घर–घर, दुकान–दुकान जाकर उन्होंने स्थानीय नागरिकों को पत्रक देते हुए विपक्षी दलों के दुष्प्रचार से सावधान रहने को कहा। भट्ट ने लोगों से कहा कि उपरोक्त कानून से किसी भी भारतीय का अहित होने वाला नहीं है बल्कि पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश के प्रताड़ित एवं मजलूम लोगों को इससे जीवन जीने में मदद मिलेगी ननकाना साहब पर हुए हमले का जिक्र करते हुए उन्होंने लोगों को बताया कि किस प्रकार अल्पसंख्यकों के धार्मिक हित इन देशों में सुरक्षित नहीं है।

विपक्ष लगातार मिली हार से बौखलाया हुआ है उसे यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि तीन तलाक धारा 370 राम मंदिर के मसले बिना किसी विवाद के हल कैसे हो गए विपक्ष अपनी हताशा व निराशा के चलते भोले भाले नागरिकों को गुमराह कर रहा है। ज्ञात हो कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड ने अपने प्रत्येक कार्यकर्ता को 10 परिवारों में जनसंपर्क हेतु और आगामी 3 महीनों तक चलने वाले नागरिकता अभियान में शरणार्थियों की मदद करने को कहा है।

जनसंपर्क में प्रदेश अध्यक्ष के साथ 20 सूत्रीय कार्यक्रम उपाध्यक्ष नरेश बंसल, महानगर भाजपा अध्यक्ष सीताराम भट्ट, पार्षद सचिन गुप्ता, भाजपा मंडल अध्यक्ष बबलू बंसल, पीएल सेठ, कुलदीप विनायक, सुरेश प्रजापति, कमल प्रजापति, शिवम राणा, सुमन सेवाई, शिखा थापा, राजकुमार तिवारी, ज्योति प्रजापति, पंकज प्रजापति, देवनाथ, भारत भूषण आदि शामिल रहे।

युवाओं की आवाज हिंसा से दबाने की कोशिश

कैंडल मार्च निकालते कांग्रेस कार्यकर्ता।

दिल्ली में अराजक तत्वों द्वारा जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में कैम्पस में घुसकर छात्र छात्राओं पर सरिए डंडों व हथौड़ों से जानलेवा हमला किये जाने व पूरे प्रकरण में दिल्ली पुलिस का मूक दर्शक बन कर तमाशा देखने की घटना के विरोध में आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस मुख्यालय से कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च में पार्टी के सभी विधायक व पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए।

पार्टी मुख्यालय में पार्टीजनों को सम्बोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि बीजेपी व आरएसएस तथा उसके तमाम सहयोगी संगठन देश में लोकतंत्र को समाप्त करने की चरणबध्द साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में असहमति व मतभिन्नता का सम्मान होता है लेकिन आरएसएस व बीजेपी चाहती है कि देश में केवल उनकी विचारधारा जीवित रहे बाकी किसी और विचारधारा के लिए कोई गुंजाइश ना रहे। उन्होंने कहा कि हिंसा के सहारे बीजेपी सरकार देश के युवाओं व विद्यार्थियों की आवाज दबाना चाहती है लेकिन कांग्रेस दमन को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दमन का जवाब गांधी के अहिंसा के रास्ते से देगी । जेएनयू की घटना को देश के अंदर फासिस्टवाद को बेशर्मी से केंद्र सरकार का खुला समर्थन बताते हुए उन्होंने कहा कि छोटी छोटी घटनाओं पर ट्वीट करने वाले प्रधानमंत्री जी देश के सबसे महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय में इतनी विभत्स घटना पर उनसे निंदा के दो शब्द नहीं निकले। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश ने कहा कि केंद्र की सरकार देश में बेरोजगारी , महंगाई, लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था से जनता का ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है और जेएनयू का प्रकरण भी इसी का हिस्सा है। कार्यक्रम का संचालन लालचन्द शर्मा ने किया।

कैंडल मार्च में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय, विधायक ममता राकेश, विधायक फुरकान अहमद, विधायक आदेश चौहान, विधायक मनोज रावत,एआईसीसी के पूर्व सचिव प्रकाश जोशी प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना, पूर्व मंत्री शूरवीर सिंह सजवाण, पूर्व मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी, पूर्व मंत्री मातबर सिंह कंडारी, नवीन जोशी, राजेन्द्र षाह, गोदावरी थापली, जिला परवा दून अध्यक्ष गौरव चौधरी,जिला पछवा दून अध्यक्ष संजय किशोर, महानगर अध्यक्ष लाल चंद शर्मा, पूर्व विधायक राजकुमार, प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी, गिरीष पुनेड़ा, नवीन पयाल, दीप बोहरा, अष्वनी बहुगुणा, भरत षर्मा, देवेन्द्र सती, संदीप चमोली, नीनू सहगल, सीताराम नौटियाल, अशोक वर्मा, त्रिलोक सजवाण, पिया थापा, राजेश शर्मा, कमर सिद्दीकी, ललित भद्री, हरि प्रसाद भट्ट, रमेश कुमार पार्षद, इलियास अंसारी पार्षद, सागर गुरुंग पार्षद, अर्जुन सोनकर, नरेश गांधी, सावित्री थापा, अनुराधा, बाला शर्मा, रीता पुश्पवाण, नवीन रमोला, विकास नेगी, डीबी क्षेत्री, महेश जोशी, कुल्दीप चौधरी, महेश चौहान, यशपाल चौहान, आशा मनोरमा डोबरियाल शर्मा, आशा टम्टा, शोभा राम, मानवेन्द सिंह, मोहन काला, कुमार, अविनाश मणि आदि शामिल रहे।

धूमधाम से मनाया जाएगा 71वां गणतंत्र दिवस

गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में सचिवालय स्थित उनके सभा कक्ष में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक हुई। मुख्य सचिव ने इस बार विभिन्न विभागों द्वारा उनकी सफलता की कहानी को प्रदर्शित करती हुई अच्छी गुणवत्ता की मनोहर झांकियां को प्रदर्शित करने तथा झांकियों को समय से तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के साथ ही विशिष्ट महानुभावों को समय से निमंत्रण पत्र प्रेषित करने और गणतंत्र दिवस के अवसर पर उन्हें यथोचित सम्मान के साथ स्थान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोगों को राज्यपाल द्वारा सामान्य जनता को दिए जाने वाले संदेश के संबंध में विभिन्न विभागों से यथोचित सूचनाएं समय से प्राप्त करते हुए अग्रिम कार्य करें। उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपने–अपने स्तर पर गणतंत्र दिवस का भव्य आयोजन कराने में सक्रियता से सहयोग देना सुनिश्चित करेंगे।

बैठक में सचिव सूचना दिलीप जावलकर ने गणतंत्र दिवस के कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए विभिन्न विभागों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि आगामी 71वें गणतंत्र दिवस को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाये जाने के लिए सूचना विभाग, पुलिस विभाग, संस्कृति विभाग, लोक निर्माण विभाग, उद्योग विभाग, शिक्षा विभाग, स्थानीय नगर निगम, एम.डी.डी.ए. के साथ ही संबंधित जनपद के जिलाधिकारी, सेना, आई.टी.बी.पी. इत्यादि द्वारा अपने–अपने स्तर पर की जाने वाली तैयारियों और जिम्मेदारियों को समय से सम्पादित करेंगे। कहा कि गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के अनुसार 25 व 26 जनवरी की सायं को मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, नगर निगम और गैर सरकारी संस्थाओं की सहभागिता से प्रमुख राजकीय भवनों को प्रकाशमान किया जाएगा। सूचना विभाग देशभक्ति गीतों का विभिन्न सार्वजनिक स्थलों–चौराहों पर प्रसारण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में टी.वी.– रेडियो के माध्यम से प्रसारण करेंगे। संस्कृति विभाग कवि सम्मेलन तथा मुख्य कार्यक्रम स्थल परेड ग्राउण्ड और राजभवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। विभिन्न जनपदों में यथासंभव मा0 प्रभारी मंत्रीगण द्वारा ध्वजाहोरण का कार्य संपन्न कराया जाएगा। परेड ग्राउण्ड में आयोजित समारोह को मनोहर बनाने के लिए वायु सेना द्वारा करतब का प्रदर्शन किया जाएगा तथा चॉपर के माध्यम से झण्डारोहण के समय फूलों की वर्षा की जाएगी। परेड ग्राउण्ड में सेना, पैरामिरिट्री आई.टी.बी.पी इत्यादि, पी.ए.सी., सिविल पुलिस, होमगार्ड, पी.आर.डी., एन.सी.सी., एन.एस.एस एवं स्काउट गाईड्स आदि द्वारा परेड में प्रतिभाग किया जाएगा।

राज्य स्तर का मुख्य कार्यक्रम परेड ग्राउण्ड, देहरादून में सम्पादित होगा जिसके अंतर्गत गत वर्ष की भांति समारोह के मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल महोदया द्वारा परेड ग्राउण्ड में प्रातः 10:30 बजे ध्वजारोहण के साथ ही कार्यक्रम की शुरूआत की जाएगी। इससे पूर्व जनपद मुख्यालयों में यथासंभव माननीय प्रभारी मंत्रीगण अथवा उनकी अनुपस्थिति में अन्य मंत्रीगण अथवा मण्डलायुक्त अथवा संबंधित जिलाधिकारी द्वारा ध्वजाहोरण किया जाएगा। तत्पश्चात् सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जाऐंगें। साथ ही सचिवालय, विभागाध्यक्ष कार्यालयों एवं शासकीय कार्यालयों में प्रात 9:30 बजे संबंधित कार्यालयाध्यक्ष, प्रभारी द्वारा ध्वजाहोरण किया जाएगा। इस अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक अभिसूचना एवं सुरक्षा उत्तराखण्ड वी विनय कुमार, प्रभारी सचिव पंकज पाण्डेय, उप महानिरीक्षक गढ़वाल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून अरूण मोहन जोशी, जिलाधिकारी देहरादून सी. रविशंकर, उपाध्यक्ष एम.डी.डी.ए डॉ आशीष श्रीवास्तव, महानिदेशक सूचना मेहरबान सिंह बिष्ट सहित सेना, संस्कृति, लोक निर्माण विभाग सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रदेश कांग्रेस की नई टीम को लेकर घमासान चरम पर

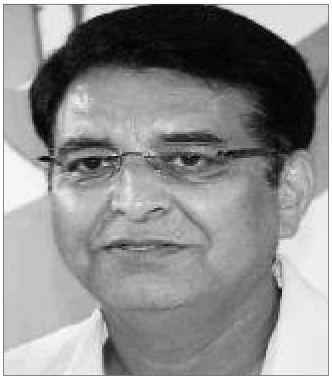

कई रूठों को मनाना पार्टी आलाकमान के लिए अब भी चुनौती

देहरादून। वर्तमान में उत्तराखण्ड कांग्रेस में राजनिति उथल पुथल के दौर से गुजर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की कार्यशैली को शुरू से ढीला ढ़ाला माना जाता है। यही वो कारण के कि कांग्रेस का एक धड़ा शुरू से ही प्रीतम सिंह के खिलाफ मोर्चा खोले रहा। अब नई कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारणी का चुनाव इस अन्दाज में होना है। जिससे 2022 में जीत का सेहरा भी कांग्रेस के सिर बध जाए और चुनाव के दौरान कोई गुटबाजी भी सामने न आए। इसलिए राजनीतिक गलियारों में कयासों का बाजार गर्म है।

कड़ाके की ठंड के बीच कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में राजनीति सरगर्मी तेज है । इधर सूत्रों का यहां तक कहना है कि जब तक पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का आर्शिवाद पूरी तरह से कांग्रेस की नई कार्यकारणी को प्राप्त नही होगा तो इस बार फिर से कांग्रेस चुनाव तक आपसी कलह से गुजरती रहेगी। जिसका खामियाजा चुनाव में भी भुंगतना पड़ सकता है। कांग्रेस की पुरानी प्रदेश कमेटी भंग होने के बाद अब इंतजार नई कमेटी का हो रहा है पर सवाल है कि टीम प्रीतम का साइज क्या होगा? यहां मामला पार्टी के विभिन्न गुटों के बीच एडजस्टमेंट का है और इसी नई टीम के भरोसे प्रीतम सिंह को 2022 का चुनाव लड़ना और जीतना है। इधर हर कार्यकर्ता इस कोशिश में है कि किसी तरह नई प्रदेश कमेटी में जगह मिल जाए। राजनीतिक गलियारो में खबर है कि प्रीतम सिंह की नई टीम का ऐलान 10 दिन के अंदर हो जाएगा और इंदिरा, हरीश, किशोर के समर्थकों को भी एडजस्ट किया जाएगा। सूत्रों का दावा है कि नई कमेटी 110 से 120 सदस्यों की होगी पर प्रीतम सिंह अभी खुलकर कुछ कहना नहीं चाहते। प्रीतम सिंह की नई टीम पर मुहर दिल्ली से लगेगी पर काम उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं को करना है। नेता विपक्ष इंदिरा हृदयेश कहती हैं कि नई टीम में ऐसे पुराने नेताओं को जगह दी गई है जिन्होंने पार्टी के लिए संघर्ष किया है। ऐसे लोगों को शामिल किया गया है जिन्होंने पहले पार्टी का नेतृत्व किया है।

पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय नई टीम को लेकर आशंकाएं जता देते हैं। वह कहते हैं कि अगर सभी को साथ लेकर चलेंगे, जिसका जितना योगदान है उतनी जगह देंगे तो 2022 में कांग्रेस इस स्थिति में होगी कि बीजेपी को टक्कर दे पाए। साथ ही वह कहते हैं कि अगर अगर हाल बीते ढाई साल जैसा रहा तो कुछ नहीं बदलने वाला।

प्रदेश कांग्रेस की नई कमेटी 50 सदस्यों की होगी, सौ की या डेढ़ सौ की इससे ज़्यादा फर्क एडस्टमेंट और एकजुटता से पड़ने वाला है। नई कार्यकारिणी में प्रीतम सिंह, हरीश रावत, इंदिरा हृदयेश और किशोर उपाध्याय का रोल अहम होगा। इन्हीं की एकजुटता और एडजस्टमेंट से तय होगा कि 2022 में कांग्रेस जीतेगी या नहीं.।

पुलिस कप्तान ने काफी हद तक सुधार दी ट्रैफिक की समस्या

इकराम अंसारी
ब्यूरो चीफ, देहरादून

“अतिक्रमण करने वाले भी दिखने लगे सड़कों से गायब”

दून के पुलिस कप्तान का कार्यभार सभालते ही अरूण मोहन जोशी ने शहर की व्यवस्था को काफी हद तक सुधार दिया है। जहां पल्टनबाजार का अतिक्रमण एक समय चुनौती बना हुआ था तो वही शहर में ट्रैफिक बाधित होना आम बात हो गयी थी। किन्तु अरूण मोहन जोशी ने दून के पुलिस कप्तान का पदभार सभालते ही शहरवासियों की समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए सबसे पहले तो ट्रैफिक को ठीक करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी।

एक समय था कि जब जब परेड मैदान के चारों ओर का पूरा इलाका अतिक्रमण से पटा हुआ था। पुलिस की कोई कार्ययोजना अतिक्रमणकारियों के आगे बौनी साबित हो रही थी। लैंसडॉन चौक से लेकर कनक चौक उसके बाद कनक चौक से लेकर सर्वेचौक तक जाने वाली गाड़ियों को रेंग रेंग करना चलना पड़ता था। लेकिन पुलिस कप्तान पद पर काबिज होते ही अरूण मोहन जोशी ने शहरवासियों इस सबसे बडी समस्या को ध्यान में रखकर अपनी गतिविधियों को अन्जाम देकर शहर की व्यवस्था को चॉकचौबंद करने का काम कर दिखाया है।

क्राईम कंट्रोल के मामले में पुलिस कप्तान ने अपने अल्प कार्यकाल में जो कर दिखाया है वो किसी से छिपा नही है। प्रेमनगर सर्राफा लूट में पुलिस ने कप्तान के नेतृत्व में जितनी मुस्तैदी से काम किया है। साथ कई हत्याओं का लूट की वारदातों का काफी कम समय में खुलासा करवाने का श्रेय भी कप्तान को जाता है। पुलिस कप्तान की कार्यशैली से जनता में सुरक्षा की भावना जागने लगी है। कुछ मामलों के लिए तो पुलिस कप्तान के कार्यकाल में हमेशा जाना जाता रहेगा।

आलम यह है कि पल्टनबाजार के भीतर आज की तारीख में अतिक्रम नाम की कोई चीज नही रह गयी है। लोग आराम से बाजार में खरीदारी करके आराम से ही अपने गंतव्यों को चले जाते है।

सारे मजहबों का मकसद अमन और मुहब्बत फैलाना

"आपसी खाई मिलन, साझेदारी के जज्बे से पाटा जा सकता"

अमन रहमान

लेखक

समय गुजरते-गुजरते हमारा समाज मजहव, जाति, रंग, नस्ल आदि के मुद्दों पर अलग-अलग वर्गो में बंट गया है। हम हमेशा खुद को दूसरों से खुदपरस्ती, खुद मुख्तारी और मजहबी अलगाववाद की वजह से खुद को औरो से अलग और खुसूसी मानने लगते हैं। हालांकि यह खाई आपसी मिलन, साझेदारी के जज्बे से पाटा जा सकता है और आपसी खाई ताल-मेल से भरी जा सकती है।

भगवत, गीता, कुरान और बाइबल एक सुर में कहती है कि सभी को दूसरों से उतना ही प्रेम करना चाहिए जितना वह खुद से करता है।

अल्लाह अपने बनाए इंसानों को साथ-साथ और मुहब्बत से रहते हुए देखना चाहता है। पवित्र कुरान कहती है कि सारी मानव जाति आदम और हव्वा से शुरू हुई है। यह समझने वाली बात है कि कोई क्यों खुद को दूसरों से सिर्फ इस बात के लिए अलग समझेगा क्योंकि उसकी पूजा करने की विधि, खान-पान का तरीका तथा विरासत दूसरों से अलग है। मजहब से परे सभी पवित्र किताबें (भगवत, गीता, कुरान और बाइबल) एक सुर में कहती है कि सभी को दूसरों से उतना ही प्रेम करना चाहिए जितना वह खुद से करता है।

हिन्दू धर्म की किताबें 'एकमेव अद्वितीय ब्रह्म सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति' पर जोर देती है जिसका मतलब है भगवान एक ही है, चाहे उसके किसी आकार रूप की पूजा करे, अन्त में उसे ही पहुंचती है। इसी प्रकार कुरान कहती है की अल्लाह एक है और उसका कोई आकारध्तस्वीर नहीं है तथा वह अपनी दया सभी जीवों पर बिना किसी भेदभाव के बरसाता है। दुर्भाग्य से हम इन पवित्र किताबों को ठीक से समझ नहीं पाए जिसकी वजह से दुनिया में समाज के इतने टुकड़े हो गए। अगर कोई व्यक्ति बहुत अमीर बन जाता है तो वह बहुत खुश होता है लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति अमीर बन जाए तो उसे यह बात हजम नहीं होती है। ऐसा केवल उसकी जलन और घमण्ड की वजह से होता है। इस समस्या का केवल एक ही हल है, सभी इंसानों को अपना ही खून समझें और सभी से वैसीमुहब्बत करो जैसा आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से करते हो।

यह सूफीवाद का भी सार है जो कहता है कि अली इंसान (अच्छा इंसान) और अल कामिल (पूरा इंसान) हीसच्चे इंसान से एक जैसा व्यवहार कर सकता है। हमें चाहिए कि भगवान को खुद में बसा लें और न केवल रूह को पवित्र करे बल्कि समाज की भलाई के लिए भी हमेशा तैयार रहें। अल्लाह दुनिया में अमन, मुहब्बत और भाईचारे को बनाने/मजबूत करने/फैलाने की हमारी कोशिशों में मदद करता है और करता रहेगा।

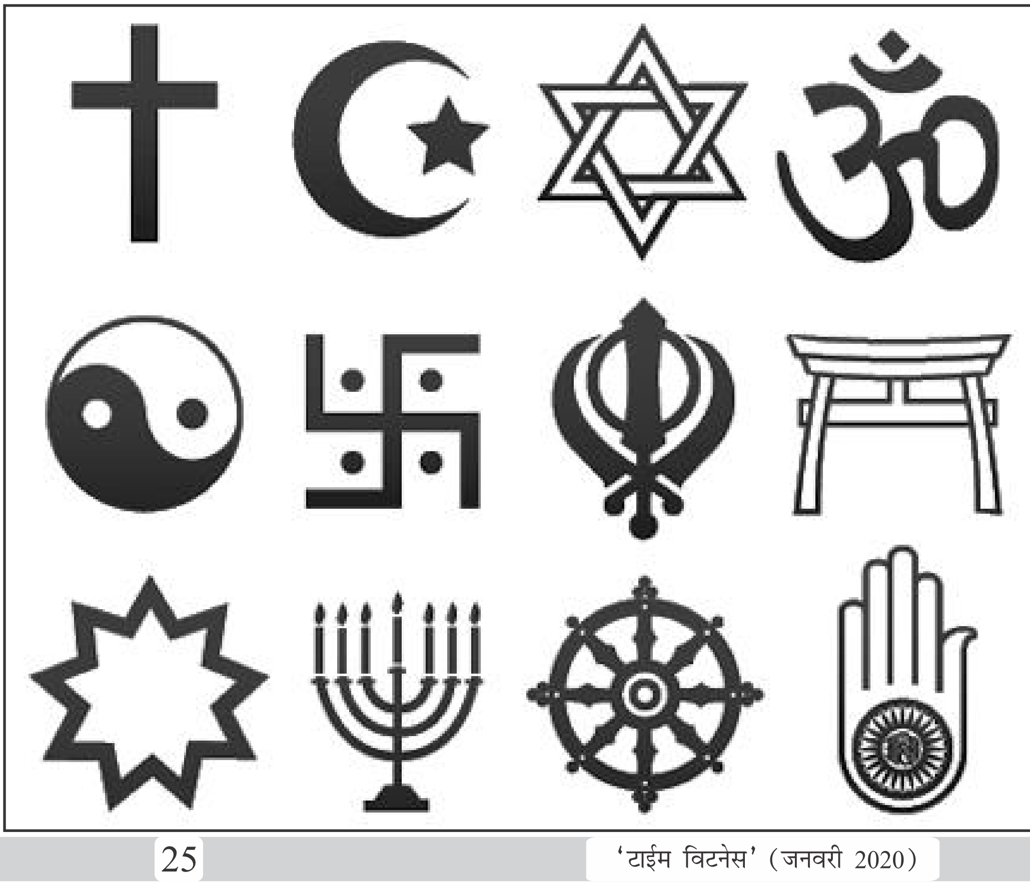

शिक्षक के रूप में करियर बनाएं

नम्रता जायसवाल

> "समाज को अच्छे शिक्षकों की हमेशा जरूरत होती है"

भारत व अन्य देशों में समाज निर्माण के लिए शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षक एक सभ्य समाज के निर्माण में मजबूत स्तंभ होते हैं। हमारे यहां शिक्षक होना गर्व की बात होती है, इसलिए कई माता-पिता अपने बच्चों को बड़े होने पर शिक्षक बनने की सलाह देते हैं। एक शिक्षक के रूप में करियर बनाने पर आप मान-सम्मान और अच्छी तनख्वाह पाकर अपना जीवन-यापन कर सकते हैं। समाज को अच्छे शिक्षकों की हमेशा जरूरत होती है। एक शिक्षक का विद्यार्थी के जीवन में, उनके माता-पिता की नजरों में अलग ही ओहदा होता है।

यदि आपको शिक्षक बनने में रुचि है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको यह चयन करना होगा कि आपका रुझान किस उम्र के विद्यार्थियों को पढ़ाने में है।

एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थी के जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदल देता है। शिक्षक होना अपने आप में कोई आसान काम नहीं है, इसके लिए शैक्षणिक योग्यता के साथ ही व्यक्तिगत योग्यता होना भी अनिवार्य है। यदि आपको शिक्षक बनने में रुचि है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको यह चयन करना होगा कि आपका रुझान किस उम्र के विद्यार्थियों को पढ़ाने में है। विद्यार्थियों की उम्र के हिसाब से आपकी शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता भी अलग-अलग होगी।

पहले आप सुनिश्चित कर लें कि आप प्ले स्कूल, प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, कॉलेजों व विश्वविद्यालय या अन्य किस शैक्षणिक संस्थान में पढ़ाना चाहते हैं। इन सभी में शिक्षक के रूप में पद पाने के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता कुछ इस प्रकार होनी चाहिए:-

1. प्री स्कूल के टीचर बनने के लिए आपको 'नर्सरी टीचर ट्रेनिंग' यानी कि 'NTT' में एक साल का प्रमाणपत्र या डिप्लोमा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है।

2. नर्सरी या किंडरगार्टन में टीचर बनने के लिए आपको मोंटेसरी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इस न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बाद आप इन स्कूलों में टीचर बन सकते हैं।

3. प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर शिक्षक बनने के लिए आपको केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि 'CTET' पास करनी होगी। आप शिक्षा-स्नातक यानी कि B-Ed की डिग्री भी ले सकते हैं। अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए आप आगे और भी पढ़ते हुए शिक्षा में परास्नातक (एमएड) M-Ed भी कर सकते हैं। इसे करना आपकी पद उन्नति के लिए लाभदायक होगा।

4. यदि आपको योगा, खेल व शारीरिक फिटनेस का ट्रेनर बनना हैं, तब आपके लिए इसी विषय में ज्ञान व डिग्री लेनी अनिवार्य है।

5. कॉलेज व विश्वविद्यालयों में शिक्षक बनने के लिए आपके पास पसंदीदा विषय में विशेषज्ञता प्रदान करती हुई डिग्री होनी चाहिए। आप आगे M-Phil व Ph-D भी कर सकते है। आपकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार ही यहां पर आपको पद मिलेगा।

6. यदि आप UGC द्वारा आयोजित करवाई जाने वाली NET परीक्षा पास कर लेते हैं, तब भी आप लेक्चरर व कॉलेज के अध्यापक बन सकते हैं। इस परीक्षा को पास करने के बाद आप विभिन्न कॉलेजों में भर्ती के लिए आवेदन दे सकते हैं।

सोते समय न रखें दक्षिण की ओर सिर, हो सकता है नुकसान

घर के पूर्व एवं ईशान दिशा में बड़ी शाखा एवं मोटी पत्तियों वाले बड़े पेड़ को नहीं लगाना चाहिए।

फेंग शुई का एक सिद्धांत है, कि जहां समस्या है वहां उसका समाधान भी है। वास्तु शास्त्र के सिद्धांत पूर्णतः वैज्ञानिक आधार पर बने हैं। इस बात की पुष्टि हम कुछ वास्तु सिद्धांतों के विश्लेषण से कर सकते हैं।

सोते समय सिर दक्षिण में :– मनुष्य का सिर उत्तरी ध्रुव और पैर दक्षिण ध्रुव में होने से दोनों में विकर्षण पैदा होगा परिणामस्वरूप मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह और नींद में बाधा पैदा होने से तनाव उत्पन्न होगा। इसी कारण वास्तु शास्त्र के अनुसार अच्छे स्वास्थ्य के लिए सोते समय सिर दक्षिण में व पैर उत्तर दिशा की ओर होने चाहिए।

पूर्व दिशा में आंगन :– घर का आंगन पूर्व दिशा में बनाना चाहिए। ताकि सूर्य की जीवनदायी प्रातः कालीन किरणों का अधिक से अधिक लाभ आपको मिल सके, और प्रातः काल धूप स्नान किया जा सके।

दीवारें ऊंची व मोटी होनी चाहिए :– प्रातः कालीन सूर्य की किरणें तो लाभदायक होती हैं परंतु दोपहर के समय जब सूर्य पश्चिम दिशा में ज्यादा तेज गर्मी फैला रहा होता है तब उस समय सूर्य की किरणें हानिकारण होती है। उन हानिकारक किरणों के संपर्क में हम कम से आएं, इस कारण वास्तुशास्त्र में दक्षिण–पश्चिम दिशा में ऊंची व मोटी दीवार बनाने की सलाह दी जाती है।

पूर्व दिशा में पेड़ :– घर के पूर्व एवं ईशान दिशा में बड़ी शाखा एवं मोटी पत्तियों वाले बड़े पेड़ को नहीं लगाना चाहिए। यह पेड़ प्रातःकालीन सूर्य की सकारात्मक किरणों को घर में प्रवेश करने में रुकावट पैदा करते हैं।

ईशान कोण में पानी :– ईशान कोण में स्थित पानी के स्त्रोत पर पड़ने वाली प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पानी में पैदा होने वाले हानिकारक वैक्टीरिया और कीटाणुओं आदि को नष्ट करती हैं। विज्ञान ने भी स्वीकार किया है कि सूर्य की किरणों में यह शक्ति होती है।

आग्नेय कोण में रसोईघर :– आग्नेय कोण में स्थित रसोई घर में पूर्व दिशा से प्रातः कालीन सूर्य किरणें प्रवेश करती हैं। जो रसोई में पैदा होने वाले हानिकारण वैक्टीरिया एवं कीटाणुओं को नष्ट कर देती हैं।

सभार : नई दुनिया

हृदय रोगी सर्दी के मौसम में रखे अपना खास ख्याल

सर्दी के मौसम में हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती हैं। इसके कई कारक हो सकते हैं, सर्दी के मौसम का आपके हृदय पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे समझना बेहद जरूरी है। यह कहना है सिटी हॉर्ट के चेयरमैन डॉ. संजय गांधी का। उन्होंने बताया कि सर्द मौसम से रक्त का संचार प्रभावित हो सकता है, रक्त का संचार सीमित हो सकता है, इससे रक्त धमनियां सीमित हो सकती हैं और इससे हृदय में कम मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचती है। इन सभी कारकों के चलते हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती हैं।

डॉ संजय गांधी ने बताया कि सर्दी से खून के थक्कों के जमने की आशंका बढ़ जाती है, जिससे हार्ट अटैक आ सकता है और लकवा भी मार सकता है। सर्दी के मौसम में खुद को गर्म महसूस कराते हुए अपने हृदय की प्रतिरक्षा करना बेहद जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि हृदय रोगी जितना भी हो सके बाहर न निकलें। ठंडा खाना और ठंडे पेय पदार्थों का सेवन न करें और गर्म खाने को प्राथमिकता दें। खान–पान की स्वस्थ आदतें अपनाएं। छुट्टी का मौसम होने के नाते लोग अक्सर अस्वस्थ तरह के भोजन का सेवन करते हैं, शराब और धूम्रपान का सेवन करते हैं और ऐसे में लोग अपना वजन बढ़ा लेते हैं।

डॉ गांधी ने कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति को पहले से ही हृदय संबंधीत बीमारी है, तो सर्दी के मौसम में और भी सावधान रहने की जरूरत है। बुजुर्ग लोगों खासकर 65 साल से अधिक उम्र के लोगों को सर्दी के मौसम में अपना ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि हेल्दी डायट एवं नियमित व्यायाम से सर्दी में उच्च रक्तचाप से बचा जा सकता है। जिन्हें पहले से उच्च रक्तचाप की शिकायत है, उन्हें रक्तचाप को कंट्रोल करने के लिए नियमित रूप से एंटी हायपरटेंसिव दवाईयां लेनी चाहिए। उन्होंने बताया कि

डॉ संजय गांधी
वरिष्ठ फिजिशियन व चैयरमैन
सिटी हार्ट सेंटर

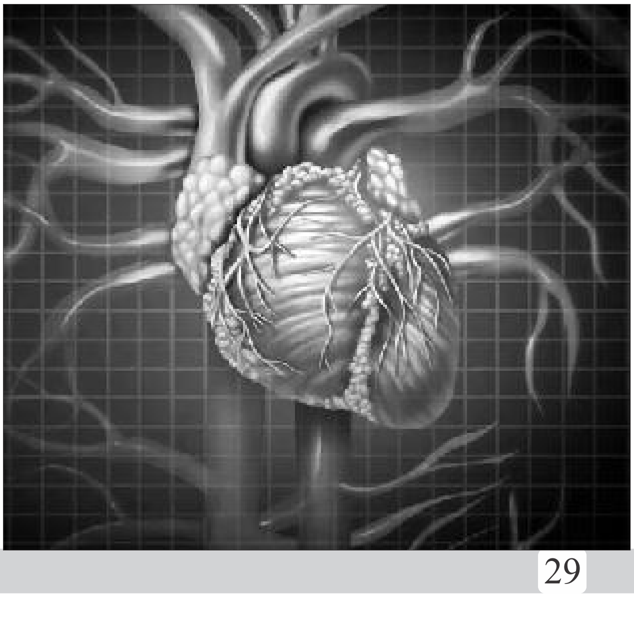

फ्लू से बुखार जैसे लक्षण हो सकते हैं जिससे हृदय की धड़कन तेज हो जाती है। इससे ऑक्सीजन युक्त रक्त की मांग बढ़ जाती है। फ्लू से डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, जिससे रक्तचाप कम होने की संभावना कम हो जाती है। इन बदलावों से हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ जाता है। जिन लोगों को पहले से हार्ट अटैक आने का खतरा होता है, इन बदलावों से उन्हें हार्ट अटैक आने की आशंका बढ़ जाती है।

डॉ गांधी ने कहा कि हाल ही में जारी किये गये रिपोर्ट्स से साबित होता है कि इंफ्लूएंजा। (भ्फ्छ) की वजह से गंभीर किस्म का मायोकार्डिटिस और कार्डियोमैयोपैथी हो सकता है। ऐसे में हृदय को रक्त संचारित करने की प्रक्रिया में अवरोध पैदा होता है, जिससे हार्ट फेल्यर की आशंका बढ़ जाती है। इंफ्लूएंजा से बचने के लिए हर साल फ्लू का एक इंजेक्शन लीजिए। अगर आप में फ्लू के लक्षण नजर आएं, तो खूब आराम करें और भारी मात्रा में तरल पदार्थ का सेवन करें। अगर हालत में सुधार न आये, तो चिकित्सीय इलाज की अवहेलना न करें। डायबिटीज और डिस्लिपिडेमिया जैसी गंभीर बीमारी का उचित इलाज कराएं।

नेलांग घाटी: इसकी खूबसूरती देखने के लिए दूर-दूर से आते हैं लोग

"पर्यटकों के लिए यह सबसे ज्यादा खूबसूरत जगह है"

उत्तरकाशी जिले में स्थित नेलांग घाटी बेहद मनोरम और सुंदर है. इसकी खूबसूरती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस जगह के प्रेमी विदेशी भी हैं। इस जगह की कई और खासियत हैं, जिन्हें जान कर आप भी यहां घूमना पसंद करेंगे। नेलांग घाटी की ऊंचाई समुद्र तट से 11,000 फीट ऊंची है, इस वजह से यहां साल भर बर्फ को देखा जा सकता है। 1962 में भारत-चीन के बीच लड़ाई के बाद घाटी को हमेशा के लिए पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया था।पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगभग 52 साल बाद नेलांग घाटी को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। नेलांग घाटी ना सिर्फ सुंदर जगह है बल्कि भारत-चीन के बीच बहुत बड़ा व्यापारिक रास्ता हुआ करता था।

पर्यटकों के अनुसार इसकी घाटी रोमांच पैदा करने वाली है इस घाटी की खूबसूरती को देखने के लिए लोग दूर–दूर से आते हैं। यहां आने के बाद पर्यटकों को नेलांग घाटी में बना वुडेन ब्रिज देखने को मिल सकता है। इस ब्रिज की सबसे खास बात है कि यह कभी भारत–तिब्बत के बीच व्यापार का केंद्र रहा था। पहाड़ी पेड़ों के अलावा यहां हिम तेंदुआ और हिमालयन ब्लू शीप देखने को मिल जाते हैं। पर्यटकों का कहना है कि घाटी को देख कर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो यह तिब्बत का ही प्रतिरूप हो। कई पर्यटकों का मानना है कि यह जगह लद्दाख से भी बेहतर है. भारत में कई ऐसी जगह हैं जो पर्यटन के लिए बहुत ही उपयुक्त हैं। तेलांग घाटी उन्हीं जगहों में से एक है। 17वीं शताब्दी में पेशावर के पठानों ने समुद्रतल से 11 हजार फीट की ऊंचाई पर उत्तरकाशी जिले की नेलांग घाटी में हिमालय की खड़ी पहाड़ी को काटकर दुनिया का सबसे खतरनाक रास्ता तैयार किया था। पांच सौ मीटर लंबा लकड़ी से तैयार यह सीढ़ीनुमा मार्ग (गर्तांगली) भारत–तिब्बत व्यापार का साक्षी रहा है। सन् 1962 से पूर्व भारत–तिब्बत के व्यापारी याक, घोड़ा–खच्चर व भेड़–बकरियों पर सामान लादकर इसी रास्ते से आवागमन करते थे। भारत–चीन युद्ध के बाद दस वर्षों तक सेना ने भी इस मार्ग का उपयोग किया। लेकिन, पिछले 40 वर्षों से गर्तांगली का उपयोग और रखरखाव न होने के कारण इसका अस्तित्व मिटने जा रहा है।

उत्तरकाशी जिले की नेलांग घाटी चीन सीमा से लगी है। सीमा पर भारत की सुमला, मंडी, नीला पानी, त्रिपानी, पीडीए व जादूंग अंतिम चौकियां हैं। सामरिक दृष्टि से संवेदनशील होने के कारण इस क्षेत्र को इनर लाइन क्षेत्र घोषित किया गया है। यहां कदम–कदम पर सेना की कड़ी चौकसी है और बिना अनुमति के जाने पर रोक है। लेकिन, एक समय ऐसा भी था, जब नेलांग घाटी भारत–तिब्बत के व्यापारियों से गुलजार रहा करती थी। दोरजी (तिब्बत के व्यापारी) ऊन, चमड़े से बने वस्त्र व नमक को लेकर सुमला, मंडी, नेलांग की गर्तांगली होते हुए उत्तरकाशी पहुंचते थे। तब उत्तरकाशी में हाट लगा करती थी। इसी कारण उत्तरकाशी को बाड़ाहाट (बड़ा बाजार) भी कहा जाता है। सामान बेचने के बाद दोरजी यहां से तेल, मसाले, दालें, गुड़, तंबाकू आदि वस्तुओं को लेकर लौटते थे।

फूलों की घाटीः धरती पर आलोकिक प्राकृतिक नजारा

ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक एस स्मिथ और आरएल होल्डसवर्थ उत्तराखंड में स्थित इस फूलों की घाटी की सुंदरता पर मोहित हो गए थे। फूलों की इस खूबसूरत घाटी का पता सबसे पहले ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक एस स्मिथ और उनके साथी आर एल होल्डसवर्थ ने वर्ष 1931 में लगाया था। वह अपने कामेट पर्वत के अभियान से लौट रहे थे। इस घाटी की खूबसूरती पर वे इस कदर मोहित हुए कि एक बार फिर 1937 में यहां लौटे। बाद में उन्होंने वर्ष 1938 में "वैली ऑफ फ्लॉवर्स" नामक एक पुस्तक का प्रकाशन किया। माना जाता है कि इस घाटी में अलग–अलग फूलों की 500 से अधिक प्रजातियां हैं।

यहाँ सामान्यतः पाये जाने वाले फूलों के पौधों में एनीमोन, जर्मेनियम, मार्श, गेंदा, प्रिभुला, पोटेन्टिला, जिउम, तारक, लिलियम, हिमालयी नीला पोस्त, बछनाग, डेलफिनियम, रानुनकुलस, कोरिडालिस, इन्डुला, सौसुरिया, कम्पानुला, पेडिक्युलरिस, मोरिना, इम्पेटिनस, बिस्टोरटा, लिगुलारिया, अनाफलिस, सैक्सिफागा, लोबिलिया, थर्मोपसिस, ट्रौलियस, एक्युलेगिया, कोडोनोपसिस, डैक्टाइलोरहिज्म, साइप्रिपेडियम, स्ट्राबेरी एवं रोडोडियोड्रान इत्यादि प्रमुख हैं। फूलों की घाटी में पुष्पाती नदी बहती है। यूनेस्को ने नन्दा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को सम्मिलित रूप से विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। यह उद्यान 87.50 किमी क्षेत्र में फैला हुआ है। फूलों की घाटी को सन 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था।

फूलों की घाटी तक पहुँचने के लिए चमोली जिले का अन्तिम बस अड्डा गोविन्दघाट 275 किमी दूर है। जोशीमठ से गोविन्दघाट की दूरी 19 किमी है। यहाँ से प्रवेश स्थल की दूरी लगभग 13 किमी है जहाँ से पर्यटक 3 किमी लम्बी व आधा किमी चौड़ी फूलों की घाटी में घूम सकते हैं। मान्यता है कि त्रेता युग में राम–रावण युद्ध में घायल लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी खोजते हुए हनुमान यहां तक आ गए थे। उन्हें संजीवनी बूटी यहीं के पहाड़ों पर मिली थी।

'दिलीप कुमार' से 'ए आर रहमान' बनने तक का सफर

ए. आर. रहमान आज अपना 53वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। बचपन से ही रहमान म्यूजिक में काफी टैलंटेड थे और बॉलिवुड से लेकर हॉलिवुड तक में वह पॉप्युलर चेहरा हैं। म्यूजिक कम्पोजर ए. आर. रहमान के पिता आर.के. शेखर फिल्म–स्कोर कम्पोजर थे और बचपन से ही अपने पिता के साथ वह स्टूडियो जाया करते थे।

स्कूल के दिनों में रहमान एक बैंड का हिस्सा भी रहे। 9 साल की उम्र में पिता का निधन हो गया और हालात कुछ ऐसे बने कि रहमान को पढ़ाई या संगीत में से किसी एक को चुनना पड़ा। घर की हाल ठीक नहीं थी, जिसके बाद उन्होंने अपनी मां से बात करने के बाद म्यूजिक को चुना। म्यूजिक से खास लगाव ने उनके सारे दुख दूर कर दिए और उनका यही पैशन आज उन्हें दुनिया के नामी संगीतकारों में शुमार करता है।

ए.आर. रहमान का पूरा नाम (अल्लाह रक्खा रहमान) है, जो पहले हिन्दू थे और उनका नाम ए. एस. दिलीप कुमार था। सुनने में आया है कि दिलीप भी नाम इसलिए रखा गया था, क्योंकि उनके पिता को दिलीप कुमार काफी पसंद थे। कहते हैं कि एक बार उनकी छोटी बहन काफी बीमार हो गई और वह जिंदगी और मौत से जूझने लगी। रिपोर्ट्स बताते हैं कि बहन के लिए उन्होंने खूब प्रार्थना की और फिर उनकी मुलाकात सूफी संत करीमुल्लाह शाह कादरी से हुई। वह इस्लाम धर्म के आदर्शों और मूल्यों में यकीन करने लगे और उनकी बहन ठीक हो गई। बता दें कि उनकी मां शादी से पहले मुस्लिम परिवार से थीं। रहमान तब 23 साल के थे जब उन्होंने इस धर्म को कुबूला।

वैसे ए आर रहमान का पूरा नाम अल्लाह रक्खा रहमान है. रहमान को म्यूजिक से जितना लगाव है उतना ही उन्हें अपने परिवार से भी है. रहमान और सायरा बानो को इस शादी से तीन बच्चे हैं. बच्चों का नाम–खतीजा, अमीन और रहीमा है।

यूं तो ए आर रहमान ने अपने करियर में कई सारे सम्मान जीते हैं मगर बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि साल 2013 में कनाडा के ऑनटारियो नामक एक स्थान पर एक स्ट्रीट का नाम रहमान के नाम पर रखा गया।

रहमान को साल 2000 में पद्मश्री और साल 2010 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है. इसके अलावा वे 2 बार ऑस्कर, 2 बार ग्रैमी, और 5 बार नेशनल अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं।

ए आर रहमान के म्यूजिक में इतना प्रभाव होता है कि इसकी गूंज विदेशों में भी सुनी जाती है। सिर्फ स्लमडॉग मिलीनियर ही नहीं, ए आर रहमान के संगीत का इस्तेमाल 127 आवर्स और लॉर्ड ऑफ वॉर जैसी फिल्मों में भी किया जा चुका है।

मैने अपने क्रश के बारे में शाहरुख को बताया था : सलमान

बॉलीवुड के किंग खान ने 1993 में आई शाहरुख खान की फिल्म 'डर' से जुड़ा किस्सा शेयर किया है। इसमें शाहरुख खान ने सिरफिरे आशिक की भूमिका निभाई थी। शाहरुख ने इस फिल्म में निगेटिव रोल किया, लेकिन फिर भी वह जबरदस्त वाहवाही बटोरने में कामयाब हुए थे। इस फिल्म में शाहरुख किरण (जूही चावला) नाम की लड़की से एकतरफा प्यार करते हैं। सनी देओल भी इस फिल्म में अहम किरदार निभाते दिखाई दिए थे। अब इस फिल्म को लेकर सलमान खान ने बिग बॉस के एक एपिसोड में अपनी क्रश के बारे में खुलकर बात की और अपनी यादों के पिटारे से एक बात उजागर करते हुए मजाकिया अंदाज में कहा कि किस तरह उन्होंने अपनी क्रश किरण के बारे में सुपरस्टार शाहरुख खान को बताया और उन्होंने उसका नाम फिल्म में इस्तेमाल किया।

अभिनेता शाहरुख खान की 1993 में आई फिल्म 'डर' अभी भी सबको अच्छी तरह याद है. फिल्म में शाहरुख एक जुनूनी प्रेमी के रूप में नजर आए थे, तो वहीं अभिनेत्री जूही चावला ने फिल्म में किरण का किरदार निभाया था। शो में आए मेहमान अभिनेता अजय देवगन और उनकी पत्नी व अभिनेत्री काजोल से सलमान ने मजाक में कहा कि यह वहीं से शुरू हुआ, फिर मैंने इस बारे में शाहरुख को बताया और उसने फिल्म बना डाली। इसके अलावा कई मजेदार सवाल–जवाब भी इस शो में हुए. जब अजय देवगन से पूछा गया कि क्या कभी उन्होंने यूं ही काजोल के खाने की तारीफ की है तो इसके जवाब में अजय देवगन ने बोला कि काजोल कभी खाना नहीं बनातीं, वे शायद ही पानी भी उबाल पाएं।

वर्कफ्रंट की बात करें तो जल्द ही काजोल और अजय देवगन की 'तानाजी' रिलीज होने वाली है. वहीं सलमान खान की बात करें तो 'दबंग–3' हाल ही में रिलीज हुई है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर छप्परफाड़ तो नहीं, बढ़िया प्रदर्शन किया है। वहीं शाहरुख खान की बात करें तो 'जीरो' के बाद उनकी कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई है और न ही उन्होंने किसी नए प्रोजेक्ट की घोषणा की है।

'हमेशा अपनी हद में रही' : सोनाली

अपकमिंग फिल्म 'जय मम्मी दी' में वरिष्ठ अभिनेत्री पूनम ढिल्लों के साथ जल्द ही पर्दे पर नजर आने वाली अभिनेत्री सोनाली सहगल का कहना है कि जब उन्होंने शूटिंग शुरू की थी, तब वह इस बात को लेकर सतर्क थीं कि वह अपनी हद पार नहीं करेंगी। सोनाली ने कहा, 'पूनम जी के साथ काम करना बहुत शानदार था। मैं उनसे पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ने के दौरान मिली थी. वह काफी खुशमिजाज इंसान हैं. वह दोस्त की तरह हैं. जब हमने शूटिग की शुरुआत की थी, तब मैं इस बात को लेकर सतर्क थी कि मैं अपने हद से बाहर न जाऊं, लेकिन पूरी प्रक्रिया के दौरान उन्होंने मेरे लिए सारी चीजें बहुत आरामदायक बना दी।'

अभिनेत्री ने कहा कि पूनम ने शूटिंग के दौरान उनकी काफी मदद की. सोनाली ने कहा, 'एक कलाकार होने के नाते मेरे लिए यह बहुत अच्छा रहा, क्योंकि उन्होंने सही तरीके से काम करने में मेरी काफी मदद की और इसी वजह से स्क्रीन पर मां–बेटी की केमिस्ट्री नजर आई।' फिल्म 'जय मम्मी दी' के बारे में बात करें तो यह कॉमेडी ड्रामा नवजोत गुलाटी द्वारा लिखित और निर्देशित है। टी सीरीज के भूषण कुमार और कृष्ण कुमार और लव फिल्म्स के लव रंजन और अंकुर गर्ग द्वारा निर्मित, यह फिल्म 17 जनवरी 2020 में रिलीज के लिए तैयार है।

मैं टाईम विटनेस की सदस्यता ले रहा/रही हूं।

नाम – श्री/श्रीमती/कुमारी...जन्म तिथि.................................

पता..

....राज्य.......................................

फोन (निवास)..............................मोबाईल...ई–मेल.................................

कृपया Time Witness के नाम का डी.डी. या चेक नं..............................तिथि.......................प्राप्त करें।

बैंक का नाम...

कृपया इस फार्म को भरकर डी.डी. या चेक के साथ हमे इस पते पर भेंजे।

टाईम विटनेस, मासिक पत्रिका

शर्मा कॉलोनी, ब्राह्मणवाला, निरंजनपुर, देहरादून।

7409293012, 7078188479

अवधि	अंको की संख्या	कवर मूल्य	बचत	सब्सक्रिप्शन मूल्य
1 वर्ष	12	180	30.00	150
2 वर्ष	24	360	60	300
3 वर्ष	36	540	110	430
4 वर्ष	48	720	200	520

नियम व शर्तें

1. यह योजना केवल भारत में ही मान्य है।

2. पत्रिका साधारण डाक द्वारा भेजी जाएगी तथा डाक गुम हो जाने पर जिम्मेदारी संस्थान की नहीं होगी। सूचना प्राप्त होने पर यदि वह अंक उपलब्ध रहता है तो पुनः निशुल्क प्रेषित कर दिया जायेगा।,

3. कूरियर रजि. डाक से मंगवाने के लिए ग्राहक का कूरियर रजि. डाक खर्च अतिरिक्त वहन करना होगा।

4 सभी विवादों का निपटारा देहरादून (उत्तराखण्ड) न्यायालय के अधीन होगा।

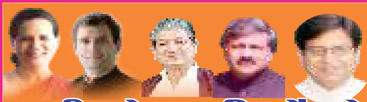

सभी प्रदेशवासियों को

नव वर्ष 2020

लोहड़ी व

मकर संक्रांति

की हार्दिक शुभकामनाएं

इरशाद अली

पूर्व ग्राम प्रधान, मेहूवाला माफी

वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, उत्तराखण्ड

सभी देश व प्रदेश वासियों को

नव वर्ष 2020

लोहड़ी एवं

मकर संक्रांति

की

हार्दिक शुभकामनाएं

मो० सुलेमान

वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं

पूर्व राज्यमंत्री उत्तराखण्ड

गुरू फॉरेन्सिक एण्ड डिटैक्टिव एजेंसी

की ओर से सभी प्रदेशवासियों को

नव वर्ष 2020

लोहड़ी एवं

मकर संक्रांति

की हार्दिक

शुभकामनाएं

1. घरेलू निगरानी
2. निजी अत्याचार की जांच
3. बच्चों की सुरक्षा व उनका उत्पीड़न
4. विवाह सम्बंधित जांच करवाना
5. पति/पत्नी में मतभेद की जांच करवाना
6. फिंगर प्रिन्ट निरीक्षण
7. हस्तलेख व हस्ताक्षर जांच
8. विवादास्पद प्रलेख जांच में दक्ष

हेड ऑफिस :– गली न0–5, मोनाल एनक्लेव, बंजारावाला, देहरादून।

ब्रांच :– नथनपुर, रिंग रोड, जोगीवाला, देहरादून।

फोन न0. 0135–2532999, 9675331055, 9568728805

E-mail:- guruforensic2015detective@gmail.com

सभी देश व प्रदेशवासियों को

नव वर्ष 2020

लोहड़ी एवं
मकर संक्रांति
की
हार्दिक शुभकामनाएं

सुनीता प्रकाश

अधिवक्ता एवं समाजसेवी
संचालिका : एस.पी. 7
स्व. श्रीमती बंचीदेवी एवं
श्री श्यामलाल जी सर्वोदय केंद्र, देहरादून

सभी देश व प्रदेश वासियों को

नव वर्ष 2020

लोहड़ी व
मकर संक्रांति
की
दिली मुबारकबाद

आर.ए. खान

निदेशक
प्रयाग आई.ए.एस अकादमी

समस्त प्रदेश व
देशवासियों को

नव वर्ष 2020

लोहड़ी व
मकर संक्रांति की
हार्दिक शुभकामनाएं

डी.एस. मान

चैयरमेन
दून इंटरनेशनल स्कूल